



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102021-230294
CG-DL-E-09102021-230294

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943

No. 307]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2021

अंतिम जांच परिणाम

मामला संख्या: एडी-(एसएसआर)-14/2021

विषय: चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अलॉय अथवा नॉन-अलॉय स्टील के कलर कोटेड/प्री-प्रीटेड फ्लैट उत्पादों" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/16/2021.—डीजीटीआर समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित सामानों पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" अथवा "एडी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. दिनांक 29 जून 2016 को, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "निर्दिष्ट प्राधिकारी" अथवा "प्राधिकारी" भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अलॉय अथवा नॉन-अलॉय स्टील के कलर कोटेड/प्री-प्रीटेड फ्लैट उत्पादों" (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के संबंध में पाटन की प्रकृति और सीमा तथा घरेलू उद्योग पर इसके हानिकारक प्रभाव की जांच करने के लिए एक जांच की शुरुआत की थी। पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए मूल याचिका मैसर्स एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड और मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी।
2. प्राधिकारी ने 20 अक्टूबर, 2016 को अधिसूचना संख्या 14/28/2016-डीजीएडी के माध्यम से प्राथमिक जांच परिणाम जारी किए और संदर्भ कीमत के रूप में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। प्राधिकारी ने 30 नवंबर, 2016 की अधिसूचना के माध्यम से उपर्युक्त प्राथमिक जांच परिणामों का शुद्धिपत्र जारी किया। केंद्र सरकार ने 11 जनवरी, 2017 को अधिसूचना संख्या 02/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत संबद्ध सामानों पर छः माह की अवधि के लिए अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया।
3. प्राधिकारी ने 30 अगस्त, 2017 को अधिसूचना संख्या 14/28/2017-डीजीएडी द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी किये और पांच वर्षों के लिए संदर्भ कीमत के रूप में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। उपर्युक्त जांच परिणामों के आधार पर, केंद्र सरकार ने 11 जनवरी 2017 से पांच वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 49/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा संदर्भ कीमत के रूप में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया।
4. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाये गये पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पूर्व में न हटाए गए हों, उन्हें लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति तक प्रभावी होना बंद हो जाएंगे और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग या उनकी ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"

5. उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उनकी ओर से किए गए विधिवत सिद्ध अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
6. और जबकि, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, इंडियन स्टील एसोसिएशन ने जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड (पूर्ववर्ती एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड) (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" अथवा "आवेदक कंपनियां" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) की ओर से सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने का अनुरोध किया। यह अनुरोध इस आधार पर किया गया था कि उपाय की समाप्ति के परिणामस्वरूप संबद्ध सामानों का पाटन जारी रहने और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के बार-बार होने की संभावना थी।

7. और जबकि, आवेदक द्वारा दायर विधिवत सिद्ध आवेदन पत्र के मद्देनजर, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में लागू शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या उस शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुसार चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 26 जुलाई, 2021 की अधिसूचना संख्या फा. संख्या 7/16/2021-डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
8. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में दिनांक 30 अगस्त, 2017 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/28/2017-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं, जिसमें संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी।

ख. प्रक्रिया

9. इस निर्णायक समीक्षा जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
- प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा भारत के राजपत्र असाधारण में 26 जुलाई, 2021 की अधिसूचना संख्या 7/16/2021-डीजीटीआर द्वारा शुरू की।
 - प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों तथा प्रयोक्ताओं और उपलब्ध सूचना के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को 26 जुलाई, 2021 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित स्वरूप और तरीके में संगत सूचना दें तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात अनुरोध दें।
 - प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को तथा संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
 - भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों सहित उन्हें भी भेजी गई थी।
 - प्राधिकारी ने संबद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

- थिसेनक्रुप स्टील यूरोप एजी
- टाटा कोरस
- एसएसएबी
- धातु व्यापार कॉमेक्स
- वोस्टाल्पिन एजी
- शंघाई मेटल कॉर्पोरेशन
- बाओस्टील ग्रुप कॉर्पोरेशन
- चीन ईस्ट स्टील एंटरप्राइज कंपनी लिमिटेड
- किंगदाओ चीन स्टील कंपनी लिमिटेड
- शंघाई कलर स्टील कंपनी लिमिटेड
- शेडोंग हवाफोन स्टील कंपनी लिमिटेड
- जियांग्सू शगांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड/झांगजीगांग शगांग हेवी प्लेट कंपनी लिमिटेड/जियांग्यिन जिंगचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स, कं, लिमिटेड, चीन जन. गण.

ड. जियांग्यिन जिंगचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स कंपनी लिमिटेड

- (vi) संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी के पास निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।
- (vii) प्राधिकारी ने अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशन को भेजी और उन्हें नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार देने की सलाह दी।

- क. कम्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लायंसेस मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
- ख. बॉम्बे आयरन मर्चेण्ट्स एसोसिएशन
- ग. प्री-इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया
- घ. सनग्रीन वेंटिलेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
- ङ. श्री राम स्टील सिंडिकेट
- च. इंडियन पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड
- छ. धातु चमक छत
- ज. बृजलाल एंड संस
- झ. कुमार निगम
- ञ. ओरिएंटल मेटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ट. एम.के.के मेटल सेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
- ठ. कुसुम मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
- ड. स्टील कंपनी
- ढ. शंकर मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड
- ण. जीएम ट्रेडर्स
- त. पीबी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
- थ. वर्ल्डपूल इंडिया लिमिटेड
- द. सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड

- (viii) किसी भी आयातक/उपभोक्ता/प्रयोक्ता एसोसिएशन ने कोई उत्तर नहीं दिया है और आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। एक आयातक, शांति आयरन ट्रेडर्स ने स्वयं को प्राधिकारी के पास एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया लेकिन समीक्षा जांच के दौरान कोई अनुरोध दायर नहीं किया।
- (ix) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अक्तूबर, 2019 से 31 मार्च, 2021 (18 माह) है। क्षति जांच अवधि 2017-18, 2018-19, 2019-20 और जांच की अवधि के रूप में मानी गई है।
- (x) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और मूल्य का परिकलन करने तथा क्षति विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- (xi) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना और आंकड़ों का सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए केवल आवश्यक संशोधन, जहां कहीं लागू हो, के साथ ऐसी सत्यापित सूचना पर विश्वास किया गया है।
- (xii) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण तथा बिक्री लागत के अनुसार क्षति रहित कीमत (जिसे यहां आगे "एनआईपी" भी कहा गया है) निकाली गई है ताकि यह

सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

- (xiii) प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु 16 सितंबर, 2021 को मौखिक सुनवाई आयोजित की। यह मौखिक सुनवाई कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। इस मौखिक सुनवाई में घरेलू उद्योग और यूरोपीय आयोग ने भाग लिया था। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में भाग नहीं लिया, उनसे लिखित अनुरोध तथा प्रत्युत्तर दायर करने का अनुरोध किया गया था।
- (xiv) जांच के दौरान और मौखिक सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में हल किया गया है।
- (xv) चूंकि संबद्ध देशों से कोई उत्पादक/निर्यातक आगे नहीं आया है और उसने कोई अनुरोध अथवा प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, अतः केवल घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- (xvi) नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी ने मामले के आवश्यक तथ्यों को प्रकट किया जो दिनांक 30.09.2021 को एक प्रकटन विवरण के रूप में उसके जांच परिणाम का आधार बनेंगे और हितबद्ध पक्षकारों को इस पर टिप्पणी करने के लिए दिनांक 4.10.2021 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर संगत सीमा तक प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है और इस जांच परिणाम में उन्हें हल किया गया है।
- (xvii) इस अंतिम जांच परिणाम में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- (xviii) प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 74.34 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान सामान

ग.1 घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 10. घरेलू उद्योग अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 11. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो प्राधिकारी ने दिनांक 30 अगस्त 2017 की मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम में निर्धारित किया था।
- 12. विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित है:

"काँइल्स में हों अथवा काँइल्स में न हों, प्री-पेंटेड, पेंटेड, कलर कोटेड अथवा ऑर्गेनिक कोटेड फ्लैट स्टील्स, चाहे 6 मिमी अथवा उससे अधिक की मोटाई की प्लेटों को छोड़कर जिंक, एल्युमिनियम जिंक अथवा किसी अन्य सबस्ट्रेट कोटिंग के मेटालिक कोटेड सबस्ट्रेट से युक्त हो अथवा नहीं।"

ये उत्पाद या तो मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के होते हैं, चाहे वे प्राइम या गैर-प्राइम गुणवत्ता के हों, या तो काँइल या सादे शीट या प्रोफाइल शीट के रूप में होते हैं, लेकिन ट्रैपेज़ॉइडल, साइनसाइडल, नालीदार या किसी अन्य प्रकार के प्रोफाइल सहित होते हैं परंतु उन तक सीमित नहीं होते हैं। ये उत्पाद विभिन्न पेंट गुणवत्ताओं और विभिन्न प्रकार के पेंट रंगों में उपलब्ध हैं, चाहे प्राइमर या किसी अन्य उपयुक्त सामग्री के साथ प्री-कोटेड हों अथवा नहीं। इन उत्पादों को या तो स्टील शीट की ऊपरी सतह पर या नीचे की सतह पर या ऊपर और नीचे दोनों सतहों पर चित्रित किया जा सकता है। इस उत्पाद की आपूर्ति गार्ड फिल्म/लेमिनेशन के साथ अथवा उसके बिना की जा सकती है।

13. विचाराधीन उत्पाद बैरियर सुरक्षा के साथ जंग के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग कई अनुप्रयोगों और क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें निर्माण, छत, दीवार, पैनलिंग, क्लैडिंग और डेकिंग, ऑटोमोटिव, सफेद सामान और उपस्कर एवं फर्नीचर आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
14. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क शीर्ष 72107000, 72124000, 72259900 और 72269990 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, आयात कुछ अन्य सीमा शुल्क टैरिफ एचएस कोड में भी देखे गए हैं, जैसे 72082790, 72085430, 72091590, 72091820, 72103090, 72104100, 72104900, 72106100, 72106900, 72107000, 72109010, 72109090, 72112350, 72112330, 72121010, 72123090, 72125090, 72126000, 72131090, 72254013। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।
15. यह नोट किया जाता है कि भारत को निर्यातित संबद्ध सामान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान तकनीकी विशिष्टियों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातित सामानों से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से परस्पर परिवर्तनीय हैं। तदनुसार, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों को संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों के लिए 'समान सामान' के रूप में माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

16. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखितानुसार परिभाषित है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान सामान के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त सामान का सामूहिक उत्पादन उक्त सामान के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित सामान के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

17. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में घरेलू उद्योग बनने घरेलू उत्पादक वही हैं जो मूल जांच में हैं। घरेलू उद्योग का जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के कुल भारतीय उत्पादन में ***% हिस्सा है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार भारत में संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन में घरेलू उद्योग के हिस्से का प्रमुख अनुपात है।

घ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

18. घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड की ओर से इंडियन स्टील एसोसिएशन द्वारा निर्णायक समीक्षा आवेदन पत्र दायर किया गया है। एसोसिएशन द्वारा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सभी संगत सूचना और दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं।
20. प्रतिभागी उत्पादकों ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और यह दावा किया जाता है कि वे भारत में संबद्ध सामानों के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के किसी भी निर्यातक से संबद्ध नहीं है। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के किसी भी निर्यातक से संबद्ध नहीं है। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड की यूरोपीय संघ में संबद्ध कंपनियां हैं लेकिन यह सिद्ध करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि संबद्ध कंपनियों ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।
21. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक कंपनियां अर्थात् आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड और जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड का भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में एक प्रमुख अनुपात है। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि आवेदक उत्पादक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड पूरा करता है।

ङ. गोपनीयता**ङ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

22. घरेलू उद्योग ने कुछ ऐसी सूचनाओं के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है, जिन्हें वह गोपनीय और व्यापार के प्रति संवेदनशील प्रकृति का मानता है। गोपनीय सूचना का पर्याप्त अगोपनीय सार उपयुक्त स्थानों पर उपलब्ध कराया गया है ताकि उसमें निहित सूचना के सार की उचित समझ हो सके।

ङ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. गोपनीयता के दावों के संबंध में किसी भी अन्य हितबद्ध पक्ष ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

ङ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
25. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5

के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

26. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
27. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर ई-मेल करें क्योंकि चल रही वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल तक वास्तविक रूप से पहुँच नहीं थी।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 सामान्य मूल्य

28. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान सामान की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान सामान की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

- (क) समान सामान की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त सामान की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त सामान का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त सामान को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी सामान का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

29. जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. संबद्ध सामानों के चीनी उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति में प्रचालन कर रहे हैं। चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य घरेलू बिक्री कीमतों और चीन जन. गण. में प्रचलित लागतों पर आधारित नहीं हो सकता है जब तक कि यह दर्शाया नहीं जाता है कि चीनी उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत प्रचालन कर रहे हैं।
- ख. मूल जांच में भी प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि चीन जन. गण. में संबद्ध उत्पाद के उत्पादक/निर्यातक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति में प्रचालन कर रहे हैं।
- ग. यूरोपीय आयोग ("ईसी") ने अपनी रिपोर्ट में चीन जन. गण. में विशिष्ट क्षेत्रों में मौजूद बाजार विकृतियों की जांच की है। यूरोपीय आयोग ने पाया है कि चीन जन. गण. में भूमि, ऊर्जा, पूंजी, कच्ची सामग्री और अन्य सामग्री इनपुट तथा श्रम से संबंधित देशव्यापी बाजार विकृतियां मौजूद हैं।
- घ. यूरोपीय आयोग रिपोर्ट ने स्टील, एल्युमीनियम, रसायन और सिरेमिक उद्योगों सहित विशिष्ट क्षेत्रों में मौजूद बाजार विकृतियों की भी जांच की। इन उद्योगों के भीतर, यूरोपीय आयोग ने पाया कि विभिन्न योजनाओं और नियामक निर्देशों के माध्यम से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और नगरपालिका स्तरों सहित सरकार के सभी स्तरों के माध्यम से चीनी सरकार के हस्तक्षेप के कारण बाजार विकृतियां हुईं।
- ङ. आईएसए के पास संबद्ध सामानों के लिए यूरोपीय संघ में उत्पादन लागत और घरेलू बिक्री कीमत के बारे में सटीक सूचना तक पहुंच नहीं है। अतः, चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य कच्ची सामग्री एचआर कॉइल के अंतरराष्ट्रीय कीमत पर विचार करके निर्मित किया गया है। अन्य कच्ची सामग्री की कीमत को घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर अपनाया गया है। कच्ची सामग्री की खपत घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर ली गई है। परिवर्तन लागतों पर घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर विचार किया गया है। घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर एसजीए लागत और वित्त लागत पर विचार किया गया है। सामान्य मूल्य निकालने के लिए 5% के लाभ मार्जिन पर विचार किया गया है।
- च. निर्यात कीमत डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के अनुसार सीआईएफ निर्यात कीमत से कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गई है। कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए संगत समायोजन किए गए हैं।
- छ. कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना के आधार पर इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ दोनों के लिए सकारात्मक और काफी है।
- ज. यह नोट किया जाना चाहिए कि चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ के उत्पादकों/ निर्यातकों ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है। अतः प्राधिकारी को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ से निर्यात के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित करने हेतु आगे कार्रवाई करनी चाहिए।

च.3. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

30. संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है। यूरोपीय आयोग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा किये गये पाटन का परिकलन में कमियां हैं। घरेलू उद्योग ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि भारत या किसी अन्य तीसरे देश को निर्यात किए जाने पर यूरोपीय संघ की कीमतें पाटित होती हैं; अथवा यह कि यूरोपीय संघ के निर्यात भविष्य में पाटित किए जाएंगे।

च.4. प्राधिकारी द्वारा जांच

31. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई।
32. चूंकि संबद्ध देशों के संबद्ध सामानों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, अतः संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

चीन जन. गण.**च.4.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण****33. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:**

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू

होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तों उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए लागू नहीं होंगे।"

34. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्धारित स्वरूप और तरीके में पूरक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

35. चूंकि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है। रिकॉर्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में, नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित अन्य पद्धतियों के संबंध में, प्राधिकारी ने "किसी अन्य उपयुक्त आधार" पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। अतः, प्राधिकारी ने कच्ची सामग्री एचआर कॉइल की अंतरराष्ट्रीय कीमत, परिवर्तन लागत और बिक्री, घरेलू उद्योग के अनुभव और उचित लाभ मार्जिन के आधार पर सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है। चीनी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

च.4.2. निर्यात कीमत का निर्धारण

36. चूंकि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, अतः डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जांच की अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य को

ध्यान में रखते हुए चीन जन. गण. से निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, सार-संभाल प्रभार, कमीशन, बैंक प्रभार और गैर-वापसी योग्य वैट के लिए समायोजन किया गया है।

यूरोपीय संघ

च.4.3 सामान्य मूल्य का निर्धारण

37. यूरोपीय संघ के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है और प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। यूरोपीय संघ से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों के सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अलग सामान्य मूल्य निर्धारित करने में सक्षम नहीं हैं और सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के सिद्धांतों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। अतः प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य कच्ची सामग्री एचआर कॉइल की अंतरराष्ट्रीय कीमत, परिवर्तन लागत और बिक्री, घरेलू उद्योग के अनुभव और उचित लाभ मार्जिन के आधार पर सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों के आधार पर निर्मित किया है। यूरोपीय संघ के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में का उल्लिखित किया गया है।

च.4.4 निर्यात कीमत का निर्धारण

38. यूरोपीय संघ के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है और प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। यूरोपीय संघ से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों के सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों और डीजीसीआईएंडएस के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार के अनुसार जांच की अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करके निर्धारित की है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, सार-संभाल प्रभार, कमीशन और बैंक प्रभारों के निमित्त समायोजन किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किये गये हैं।

च.5 पाटन मार्जिन

39. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ के लिए पाटन मार्जिन न केवल नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक भी है।

देश	उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य (भारतीय रुपये/ मी. टन)	एनईपी (भारतीय रुपये/ मी. टन)	पाटन मार्जिन (भारतीय रुपये/ मी. टन)	पाटन मार्जिन %	रेंज
चीन जन. गण.	कोई भी उत्पादक/ निर्यातक	***	51,788	***	***	35-45%
यूरोपीय संघ	कोई भी उत्पादक/ निर्यातक	***	58,389	***	***	20-30%

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

40. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. मूल जांच में प्राधिकारी ने पहले ही पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच एक कारणात्मक संपर्क स्थापित कर लिया है। अतः, निर्णायक समीक्षा में, जांचकर्ता प्राधिकारी को शुल्क की समामि और पाटन एवं क्षति के बार-बार होने की संभावना के बीच एक संपर्क स्थापित करनी चाहिए और समीक्षा के दौरान पाटित आयातों एवं क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- ख. संबद्ध देशों से आयात पूर्ण दृष्टि से और भारत में कुल आयात एवं पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी भारतीय मांग दोनों के संबंध में काफी हैं।
- ग. संबद्ध देशों के पास अत्यधिक क्षमता और सीमित या स्थिर मांग है। उन्हें निर्यात बाजारों की जरूरत है और भारत काफी और मांग वाले सबसे बड़े बाजारों में से एक है। यह भारतीय बाजार में आयात की आमद पैदा कर सकता है यदि शुल्क हटाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न बाजारों में संबद्ध देशों के विरुद्ध वर्तमान में काफी अधिक टैरिफ और व्यापार उपचारात्मक उपाय लागू हैं। यदि मौजूदा उपाय नहीं बढ़ाए जाते हैं, तो भारत बिना किसी व्यापार उपचारात्मक उपायों के संबद्ध देशों के लिए एकमात्र प्रमुख निर्यात लक्ष्य होगा।
- घ. जांच की अवधि के अंतिम छह महीनों के दौरान अर्थात् अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020 तक आयात में गिरावट कोविड-19 महामारी के कारण हुई है। कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने पर आयात बढ़ेगा।
- ङ. यूरोपीय संघ से कीमत कटौती नकारात्मक है और चीन जन. गण. से कीमत कटौती आंशिक रूप से सकारात्मक है।
- च. संबद्ध देशों से निर्यात/आयात कीमत में काफी कीमत अंतर है। प्राधिकारी को कम कीमतों पर आयात लेनदेन पर भी विचार करना चाहिए जो घरेलू बिक्री में कटौती कर रहे हैं। प्राधिकारी का आकलन औसत कीमत कटौती तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की बिक्री पर कम कीमत वाले आयात लेनदेनों के प्रभाव का आकलन करना चाहिए। चीन जन. गण. से कुल आयात का लगभग 73% और यूरोपीय संघ से कुल आयात का 35% घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से कम है।
- छ. संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क और जो क्षति जांच अवधि के दौरान लागू रहा है, संदर्भ कीमत तंत्र पर आधारित है। संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों का यह दायित्व था कि वे कीमतों को संदर्भ कीमत स्तर से ऊपर रखें।
- ज. प्राधिकारी को आयात कीमत पर विचार करके कीमत कटौती का भी आकलन करना चाहिए जो संदर्भ कीमत आधारित पाटनरोधी शुल्क लगाने से पहले विद्यमान थी।
- झ. संदर्भ कीमत आधारित पाटनरोधी शुल्क के मामले में, वास्तविक आयात कीमत पर केवल कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि पाटनरोधी शुल्क का घटक संबद्ध देशों से आयात/निर्यात कीमत में अंतर्निर्मित होता है। अतः, कीमत कटौती का आकलन आयात कीमत में 'अंतर्निर्मित' पाटनरोधी शुल्क घटाने के बाद किया जाना चाहिए। यदि प्राधिकारी मूल जांच के दौरान परिकलित औसत पाटनरोधी शुल्क को हटा देते हैं, तो कीमत कटौती काफी सकारात्मक हो जाएगी।
- ञ. सीआईएफ के रूप में सुपुर्दगी शर्तों को निर्धारित करने के लिए उत्पादकों/निर्यातकों के बीच एक परिपाटी भी है, जबकि सामग्री की सुपुर्दगी आईसीडी पर की जाती है और इसके परिणामस्वरूप रिकॉर्ड पर कीमत में आयात के पहले बंदरगाह से आईसीडी बंदरगाह तक परिवहन लागत का एक अतिरिक्त कीमत घटक शामिल होता है। सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमावली के अनुसार, आयात के पहले बंदरगाह से आईसीडी के लिए माल

हुलाई घटक को सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए मूल्य में शामिल नहीं किया जाना होता है और तदनुसार इसे पाटनरोधी जांच के लिए पहुंच मूल्य का परिकलन करते समय भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

- ट. संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों को निर्णायक समीक्षा की सटीक अवधि के बारे में पता था और इसलिए उनके लिए भारत में अपने निर्यात के लिए औसत कीमतों को अधिक रखना संभव था। प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या निर्यात कीमत में वृद्धि आर्थिक औचित्य पर आधारित है अथवा अस्थायी है।
- ठ. प्राधिकारी को केवल औसत आयात कीमत पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि जांच की अवधि के दौरान आयात कीमतें लगातार अधिक नहीं होती हैं। आयातों में काफी कीमत अंतर है और कम कीमतों पर आयात लेनदेनों के प्रभाव पर अलग से विचार करने की आवश्यकता है। कीमत अंतर की मौजूदगी संगत है क्योंकि कई भारतीय ग्राहक वे कीमतें दर्शाते हैं जिन पर आयातित सामान देश में आ रहे हैं और घरेलू उद्योग से आयातित कीमतों को बराबर रखने के लिए कहते हैं।
- ड. भारत में औसत आयात कीमतों का वर्तमान स्तर उस प्रकार के कीमत ह्रास और न्यूनीकरण को नहीं दर्शा सकता है जो एक बार संदर्भ कीमत आधारित पाटनरोधी शुल्क के रूप में दिए गए संरक्षण को हटा दिए जाने पर संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग पर लागू करने में सक्षम हैं। यदि पाटनरोधी शुल्क बंद कर दिया जाता है, तो कीमत ह्रास और न्यूनीकरण की मात्रा काफी बदल जाएगी।
- ढ. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2019-20 तक सुधार हुआ और उसके बाद जांच की अवधि (वार्षिक) के दौरान गिरावट आई।
- ण. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है। जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में सुधार वैश्विक स्तर पर स्टील की कीमतों में अस्थायी उछाल के कारण भी है। यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क संरक्षण वापस ले लिया जाता है, तो यह आगे चलकर घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नकद लाभ ने लाभप्रदता के समान प्रवृत्ति का अनुसरण किया है।
- त. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों की गुणवत्ता आयातित सामानों के बराबर है। घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और इसलिए सामग्री की उपलब्धता कोई बाधा नहीं है। वितरण की समस्या भी लगभग न के बराबर है। कई भारतीय ग्राहक उन कीमतों को दर्शाते हैं जिन पर आयातित सामान देश में आ रहे हैं और घरेलू उद्योग से आयातित कीमतों को बराबर रखने के लिए कहते हैं।
- थ. वियतनाम से संबद्ध सामानों का काफी आयात भारत में आ रहा है। वियतनाम से भारत में संबद्ध सामानों का आयात भी वास्तव में चीन जन. गण. में हो सकता है। यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि वियतनाम से संबद्ध सामानों का आयात चीन जन. गण. से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद शुरू हुआ था। नीचे दी गई तालिका स्पष्ट रूप से वियतनाम से आयात की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है:

	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2021)
वियतनाम से आयात	1,14,856	468	11,291	74,257

- द. वियतनाम से पहुंच मूल्य चीन जन. गण. से पहुंच मूल्य से कम है और नीचे दर्शाए गए अनुसार 822 अमरीकी डालर/मी. टन के संदर्भ मूल्य से भी कम है:

पहुंच मूल्य	यूनिट	जांच की अवधि (अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2021)
चीन जन. गण.	अमरीकी डॉलर/मी. टन	903.58
वियतनाम	अमरीकी डॉलर/मी. टन	816.35

41. चीन जन. गण. से जंग प्रतिरोधी स्टील उत्पादों (कोर) के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई प्रवंचनारोधी जांच में, यह निर्धारित किया गया था कि वियतनाम में उत्पादित कुछ जंग प्रतिरोधी स्टील उत्पादों के आयात पाटनरोधी शुल्क और चीन जन. गण. से कोर संबंधी प्रतिकारी शुल्क आदेशों की प्रवंचना कर रहे हैं।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

42. क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है।
43. जांच की अवधि के दौरान यूरोपीय संघ से कोई आयात नहीं हुआ है। यूरोपीय संघ से आयात कीमत अन्य देशों से औसत आयात कीमत से अधिक है और इसलिए यूरोपीय संघ से आयात के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

44. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “... पाटित आयातों की मात्रा, समान सामानों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसे सामानों के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...” घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी।
45. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा काफी मात्रा तक कीमतों का ह्रास करने अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारक जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री आय, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।
46. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोधों की जांच की गई है और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में उन्हें हल किया गया है।
47. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने के लिए आगे की कार्रवाई करने से पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है।
48. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण यथातथ्यतः घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को हल करता है।
49. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में, प्राधिकारी ने 1 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2021 तक 18 महीने की लंबी अवधि को जांच की अवधि के रूप में माना है ताकि यह घरेलू उद्योग को वर्तमान और संभावित पाटन एवं क्षति के बारे में पर्याप्त सूचना प्रदान कर सके। साथ ही, वर्तमान निर्णायक समीक्षा में एक लंबी जांच अवधि को उपयुक्त माना गया था क्योंकि 2020-21 की पहली तिमाही में व्यापार कोविड-19 से प्रभावित था और तथाकथित

पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति और क्षति की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए लंबी अवधि उपयुक्त होगी।

क. मांग का आकलन

50. प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों की मात्रा के रूप में निर्धारित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)	जांच की अवधि (अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2021)
1	संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	2,58,098	71,610	78,531	70,137	1,05,206
		प्रवृत्ति	100	28	30	27	41
2	अन्य देशों से आयात	मी. टन	1,97,677	72,529	83,119	1,06,152	1,59,228
		प्रवृत्ति	100	37	42	54	81
3	प्रतिभागी उत्पादकों की घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***
		प्रवृत्ति	100	119	133	141	212
4	अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***
		प्रवृत्ति	100	123	162	134	201
5	कुल मांग	मी. टन	18,99,000	18,93,000	23,13,000	21,56,667	32,35,000
		प्रवृत्ति	100	100	122	114	170

51. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि (वार्षिक) के दौरान मामूली गिरावट को छोड़कर, पूरी क्षति जांच अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है।

ख. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

1. आयातों की मात्रा और संबद्ध देशों का हिस्सा

52. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा के प्रभावों की जांच निम्नानुसार की गई है:

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)	जांच की अवधि (अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2021)
1	संबद्ध देश	मी. टन	2,58,098	71,610	78,531	70,137	1,05,206
क	चीन जन. गण.	मी. टन	2,54,954	71,088	76,712	69,353	1,04,029
ख	यूरोपीय संघ	मी. टन	3,145	522	1,819	785	1,177
2	के संबंध में संबद्ध देशों से आयात						
क	घरेलू उद्योग का उत्पादन	%	***	***	***	***	***

ख	खपत	%	14%	4%	3%	3%	3%
ग	कुल आयात	%	57%	50%	49%	39%	39%

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों में जांच की अवधि (वार्षिक) के दौरान समग्र रूप से और साथ ही कुल भारतीय उत्पादन, कुल भारतीय खपत और कुल आयातों के संबंध में गिरावट आई है।

ग. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

54. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में तथाकथित पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में कमी करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती।
55. तदनुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, बिक्री लागत और निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

i. कीमत कटौती

56. भारत में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली के साथ संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना करके कीमत कटौती का निर्धारण किया गया है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2021)
1	निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	***	***	***	***
2	पहुंच कीमत					
क	चीन जन. गण.	रु./मी. टन	57,110	69,400	62,956	66,115
ख	यूरोपीय संघ	रु./मी. टन	68,920	1,05,862	85,397	77,918
ग	संबद्ध देश	रु./मी. टन	57,254	69,666	63,475	66,247
3	कीमत कटौती					
क	चीन जन. गण.	रु./मी. टन	***	(***)	***	***
ख	यूरोपीय संघ	रु./मी. टन	(***)	(***)	(***)	(***)
ग	संबद्ध देश	रु./मी. टन	***	(***)	(***)	***
4	कीमत कटौती					
क	चीन जन. गण.	%	***	(***)	***	***
ख	यूरोपीय संघ	%	(***)	(***)	(***)	(***)
ग	संबद्ध देश	%	***	(***)	(***)	***

5	कीमत कटौती					
क	चीन जन. गण.	रेंज	5-15%	नकारात्मक	0-10%	0-10%
ख	यूरोपीय संघ	रेंज	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक	नकारात्मक
ग	संबद्ध देश	रेंज	5-15%	नकारात्मक	नकारात्मक	0-10%

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ से आयातों के लिए कीमत कटौती नकारात्मक है। चीन जन. गण. से आयातों के लिए कीमत कटौती आंशिक रूप से सकारात्मक है।

ii. कीमत न्यूनीकरण एवं ह्रास

58. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास कर रहे हैं और क्या इन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का न्यूनीकरण करने के लिए अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होती, प्राधिकारी क्षति की अवधि में लागतों तथा कीमतों में परिवर्तनों को नोट करते हैं।

क्रम सं.	विवरण	यूक्यूएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2021)
1	पहुँच कीमत - संबद्ध देश	रु./मी. टन	57,254	69,666	63,475	66,247
		सूचीबद्ध	100	122	111	116
2	प्रति यूनिट बिक्री की लागत - घरेलू	रु./मी. टन	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	110	99	104
3	प्रति यूनिट बिक्री कीमत - घरेलू	रु./मी. टन	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	110	101	108

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की कीमतें 2018-19 तक बढ़ीं जब आयात की कीमतें भी बढ़ रही थीं। इसके बाद, जब 2018-19 की तुलना में 2019-20 और जांच की अवधि के दौरान आयात कीमतों में गिरावट आई, उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में भी गिरावट आई।

घ. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

60. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

61. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)	जांच की अवधि (अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2021)
1	क्षमता	मी. टन	***	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	100	101	109	163
2	स्व-उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	110	113	111	166
3	जॉब कार्य उत्पादन	मी. टन	-	-	***	***	***
		सूचीबद्ध	-	-	100	154	232
4	कुल उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	110	124	128	191
5	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	110	112	102	102
6	घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	119	133	141	212

62. यह देखा जाता है कि:

- क. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान अपनी क्षमता का विस्तार किया है।
 ख. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 2019-20 तक बढ़ा लेकिन जांच की अवधि (वार्षिक) में गिरावट आई।
 ग. क्षति अवधि के दौरान कुल उत्पादन और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई।

ii. मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा

63. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच निम्नानुसार की गई है:

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)	जांच की अवधि (अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2021)
1	संबद्ध देश	%	14%	4%	3%	3%	3%
		%-रेंज	10-20	0-10	0-10	0-10	0-10

2	अन्य देश	%	10%	4%	4%	5%	5%
		%- रेंज	5-15	0-10	0-10	0-10	0-10
3	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***	***
		%- रेंज	30- 40	35- 45	35- 45	35-45	35-45

64. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2018-19 में वृद्धि हुई, फिर 2019-20 में गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि (वार्षिक) में फिर से वृद्धि हुई।

iii. मालसूची

65. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे दी गई है:-

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)
औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	112	168	110

66. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में 2019-20 तक वृद्धि हुई और उसके बाद जांच की अवधि (वार्षिक) के दौरान गिरावट आई।

iv. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय

67. लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)	जांच की अवधि (अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2021)
1	विक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	110	99	104	104
2	बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	110	101	108	108
3	लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	124	150	189	284

4	लाभ/हानि	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	104	113	134	134
5	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	124	151	187	281
6	नकद लाभ	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	104	113	133	133
7	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	124	150	185	278
8	पीबीआईटी	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	104	112	131	131
9	नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	94	80	106	106

68. यह देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

69. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच की गई है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)	जांच की अवधि (अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2021)
1	कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	101	100	104	104
2	प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/दिन	***	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	110	113	111	111
3	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/सं.	***	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	110	113	106	106

70. यह देखा जाता है कि क्षति जांच अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

vi. वृद्धि

71. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों में वृद्धि की जांच नीचे दर्शाई गई है।

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)
1	उत्पादन	***	***	***
2	घरेलू बिक्री	***	***	***
3	प्रति मी. टन लाभ/(हानि)	***	***	***
4	लाभ/(हानि) - (लाख रु.)	***	***	***
5	नकद लाभ - (लाख रु.)	***	***	***
6	पीबीआईटी - (लाख रु.)	***	***	***
7	आरओआई %	***	***	***

72. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक और कीमत मानदंड सकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं।

vii. पाटन की मात्रा

73. यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि काफी भी है।

viii. नई पूंजी जुटाने की क्षमता

74. घरेलू उद्योग में वे कंपनियां शामिल हैं, जो बहु-उत्पाद कंपनियां हैं। ये कंपनियां क्षति अवधि के दौरान काफी अच्छा निष्पादन कर रही हैं। अतः, नई पूंजी जुटाने की उनकी क्षमता बरकरार है।

ज. कारणात्मक संपर्क से संबंधित कारक

75. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना अपेक्षित होता है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या जिससे क्षति होने की संभावना है, ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति पाटित आयातों के कारण न हो। जबकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में कारणात्मक संपर्क की पहले ही जांच की जा चुकी है, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है या होने की संभावना है। इस बात की जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दे सकते हैं या उनके योगदान करने की संभावना है।

i. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

76. तीसरे देशों से आयात पूर्ण दृष्टि से और कुल आयात के संबंध में बड़े हैं।

क्रम सं.	विवरण	यूक्यूएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)	जांच की अवधि (अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2021)
1	संबद्ध देशों से	मी. टन	2,58,098	71,610	78,531	70,137	105,206

	आयात	प्रवृत्ति	100	28	30	27	41
2	अन्य देशों से आयात	मी. टन	1,97,677	72,529	83,119	1,06,152	1,59,228
		प्रवृत्ति	100	37	42	54	81

77. यह नोट किया जाता है कि गैर-संबद्ध देशों से अधिकतर आयात कोरिया गणराज्य और वियतनाम से होते हैं। कोरिया गणराज्य से आयात संबद्ध देशों से आयात कीमतों की तुलना में काफी अधिक कीमतों पर हैं। वियतनाम से भारत में संबद्ध सामानों के आयात कम कीमतों पर हैं।

ii. मांग में संकुचन और/अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

78. यह देखा जाता है कि पूरी क्षति जांच अवधि में जांच की अवधि (वार्षिक) को छोड़कर संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है।

iii. प्रौद्योगिकी का विकास

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः प्रौद्योगिकी में विकास, क्षति का एक संभव कारक नहीं है।

iv. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ

80. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं नहीं हैं जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

v. निर्यात निष्पादन

81. यह देखा जाता है कि क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निर्यात कमोबेश उसी रेंज में रहा है। किसी भी दशा में, प्राधिकारी ने अपने क्षति विश्लेषण में केवल घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है।

vi. अन्य उत्पादों का निष्पादन

82. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामान के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बिक्री किए गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभव कारण नहीं हो सकता।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

83. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर और जांच की अवधि के लिए प्रैक्टिसिंग लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित करके निर्धारित की गई है। क्षतिरहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देशों से पहुँच कीमत से की गई है।

84. क्षतिरहित का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान कच्ची सामग्री और यूटिलिटीयों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या अनावर्ती व्यय को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात्, औसत निवल अचल परिसंपत्ति प्लस औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित आय (22% की दर से कर पूर्व) की क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी, जैसा कि नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित है और उसे अपनाया जा रहा है।
85. उपर्युक्तानुसार निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रस्तावित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

देश	उत्पादक/निर्यातक	एनआईपी (भारतीय रुपये/मी. टन)	पहुँच कीमत (भारतीय रुपये/मी. टन)	क्षति मार्जिन (भारतीय रुपये/मी. टन)	क्षति मार्जिन %	रेंज
चीन जन. गण.	कोई भी उत्पादक/निर्यातक	***	66,115	(***)	(***)	(5-15)
यूरोपीय संघ	कोई भी उत्पादक/निर्यातक	***	77,918	(***)	(***)	(20-30)

घ. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

86. निर्णायक समीक्षा जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. घरेलू उद्योग के निष्पादन ने प्राधिकारी द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के सकारात्मक परिणाम के रूप में सुधार दर्शाया है। तथापि, एक बार पाटनरोधी शुल्क हटा दिए जाने के बाद चीन जन. गण. से संबद्ध सामान चीन जन. गण. में अतिरिक्त क्षमता और उनके स्थानीय बाजार में सीमित अथवा स्थिर मांग के कारण भारतीय बाजार में बेरोकटोक प्रवेश करेंगे।
- ख. माईस्टील नेटवर्क रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में 64.54 फीसदी क्षमता उपयोग के साथ, चीनी उत्पादकों के पास 11.03 मिलियन टन की बेकार क्षमताएं हैं, जिनका उपयोग भारत सहित निर्यात स्थलों के लिए विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है।

क्रम सं.	विवरण	स्रोत	मिलियन टन
क	चीन की घरेलू मांग	माईस्टील रिपोर्ट	13.50
ख	चीन से कुल निर्यात	माईस्टील रिपोर्ट	6.57
ग	कुल उत्पादन	क+ख	20.07
घ	क्षमता उपयोग	माईस्टील रिपोर्ट	64.54%
ङ	उत्पादन क्षमता	ग/घ	31.10
च	बेकार क्षमता	ङ-ग	11.03

ग. भारत काफी और बढ़ती हुई मांग वाला एक बड़ा बाजार है। जांच की अवधि (वार्षिक) में मांग लगभग 2.1 मिलियन टन है।

मांग (मी. टन)	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)	जांच की अवधि (अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2021)
	18,99,000	18,93,000	23,13,000	21,56,667	32,35,000

घ. चीन जन. गण. में बेकार क्षमता भारत में संबद्ध सामानों की कुल वार्षिक मांग के 5 गुना से अधिक है।

ङ. चीनी उत्पादकों के पास 31.10 मिलियन टन उत्पादन क्षमता है और उनकी घरेलू मांग 13.50 मिलियन टन है। इसलिए, चीनी उत्पादकों के पास निर्यात के लिए 17.60 मिलियन टन क्षमता उपलब्ध है (जो कि कुल क्षमता का 57% है), जिसका उपयोग निर्यात बाजारों के लिए किया जा सकता है।

विवरण	स्रोत	मिलियन टन
उत्पादन क्षमता	उपर्युक्त तालिका में क्रम सं. ङ के अनुसार	31.10
चीन की घरेलू मांग	माईस्टील रिपोर्ट	13.50
निर्यात के लिए उपलब्ध क्षमता		17.60
कुल क्षमता के संबंध में निर्यात के लिए उपलब्ध क्षमता		57%

च. चीन जन. गण. से भारत को कलर कोटेड स्टीर उत्पाद की औसत निर्यात कीमत अन्य देशों की निर्यात कीमत से अधिक रही है:

विचाराधीन उत्पाद	यूनिट	2018	2019	2020
शेष विश्व को एफओबी निर्यात मूल्य	अमरीकी डॉलर /मी. टन	826	737	717

स्रोत: आईएसएसबी डाटाबेस

विचाराधीन उत्पाद	यूनिट	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
भारत में आयात कीमतें	अमरीकी डॉलर /मी. टन	861	772	801

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस आंकड़े

छ. अन्य देशों की तुलना में चीन जन. गण. से निर्यातकों के लिए कीमतों के मामले में भारतीय बाजार अधिक आकर्षक है।

ज. चीन जन. गण. से तीसरे देशों को अधिकतर निर्यात पाटित और क्षतिरहित कीमतों पर हैं।

विवरण	यूनिट	पाटन मार्जिन	क्षति मार्जिन	कीमत कटौती
जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से कुल निर्यात	मी. टन	***	***	***
सकारात्मक पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन/कीमत कटौती वाले निर्यात	मी. टन	***	***	***
सकारात्मक पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन/कीमत कटौती वाले निर्यात	%	95%	38%	78%

स्रोत: आईएसएसबी आंकड़े

झ. चीन जन. गण. से तीसरे देशों को निर्यात के पर्याप्त भाग में सकारात्मक पाटन मार्जिन है। चीन जन. गण. से तीसरे देशों को अधिकतर निर्यात भी घरेलू बिक्री मूल्य और घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से काफी कम हैं। यदि पाटनरोधी शुल्क वापस लेने पर तीसरे देशों को किए गए इन निर्यातों को भारत की ओर मोड़ दिया जाता है, तो चीन जन. गण. से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की स्पष्ट संभावना है।

ञ. यूरोपीय संघ से विचाराधीन उत्पाद का वर्तमान आयात नगण्य है। तथापि, यूरोपीय संघ से कम आयात लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण भी हैं। यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो यूरोपीय संघ से आयात बढ़ने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ में संबद्ध सामान की मांग स्थिर है।

मिलियन टन	2017	2018	2019	2020
मांग*	5.32	5.25	5.54	5.25

*स्रोत: यूरोपीय संघ के उत्पादन, आयात और निर्यात पर आधारित यूरोफर और आईएसएसबी

ट. यूरोपीय संघ के पास 2020 में कम से कम 4,70,000 मीट्रिक टन की मांग से अधिक क्षमता है और 2020 में उत्पादन से अधिक क्षमता 6,90,000 मीट्रिक टन है। यूरोपीय संघ में कुल यूरोपीय संघ की मांग से अधिक अधिशेष क्षमता भारतीय क्षमता के लगभग 22% है और यूरोपीय संघ में भारती कुल यूरोपीय संघ के उत्पादन से अधिक अधिशेष क्षमता भारतीय मांग के लगभग 32% है।

मिलियन टन	स्रोत	2018	2019	2020
उत्पादन (सी)	यूरोफर	4.93	5.14	5.03
आयात	आईएसएसबी	0.94	1.00	0.83
निर्यात	आईएसएसबी	0.62	0.61	0.61
मांग (क)		5.25	5.54	5.25
क्षमता (ख)		5.60	5.84	5.72
मांग से अधिक क्षमता (ख) - (क)		0.35	0.30	0.47
उत्पादन से अधिक क्षमता (ख) - (ग)		0.67	0.70	0.69

ठ. जब भी यूरोपीय संघ में घरेलू मांग में गिरावट आई है, उत्पादकों ने निर्यात बाजारों पर ध्यान केंद्रित किया है। नीचे दी गई तालिका निर्यातों में वृद्धि और घरेलू मांग में गिरावट के बीच सह-संबंध स्पष्ट रूप से दर्शाती है:

वर्ष	मांग – (स्रोत: आईएसएसबी और यूरोफेर से लिए गए)	यूरोपीय संघ से निर्यात (स्रोत: आईएसएसबी)
2011	5.12	0.51
2012	4.58	0.64
2013	4.44	0.75
2014	4.63	0.70

ड. आईएसएसबी आंकड़ों की सहायता से आवेदक द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, यूरोपीय संघ द्वारा तीसरे देशों को निर्यात का 19% पाटित कीमतों पर है।

ढ. महत्वपूर्ण बाजार आकार वाले लगभग सभी प्रमुख देशों ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पहले ही व्यापार उपचारात्मक उपाय लगाए हैं अथवा जारी हैं। यदि पाटनरोधी शुल्क बंद कर दिया जाता है, तो इससे संबद्ध देशों से पाटित आयातों के अत्यधिक प्रवाह के कारण भारतीय घरेलू उत्पादकों को क्षति बार-बारी होगी।

ण. निम्नलिखित देशों ने संबद्ध सामानों के आयातों पर व्यापार उपचार उपाय लागू किए हैं/जारी रखे हैं:

क्रम सं.	आयातक देश	उत्पाद का विवरण	उपाय का प्रकार	देश/देशों की जांच की गई
1.	ऑस्ट्रेलिया	पेंटेड स्टील स्ट्रेपिंग	पाटनरोधी	चीन जन. गण.
2.	चीनी तैपई	जिंक और जिंक-अलॉयज वाले प्लेटेड और कोटेड फ्लैट रोलड स्टील उत्पाद	पाटनरोधी	चीन जन. गण., कोरिया
3.	मैक्सिको	कुछ कोटेड फ्लैट स्टील उत्पाद	पाटनरोधी	चीन जन. गण. और ताइवान
4.	अमेरीका	कोरोजीन-रेसिस्टेंट स्टील उत्पाद	पाटनरोधी	चीन जन. गण., इटली, कोरिया, ताइवान और भारत
5.	अमेरीका	कोरोजीन-रेसिस्टेंट स्टील उत्पाद	प्रतिकारी शुल्क	चीन जन. गण., इटली, कोरिया, ताइवान और भारत
6.	मलेशिया	प्री-पेंटेड, पेंटेड अथवा कलर-कोटेड स्टील कॉइल्स	पाटनरोधी	चीन जन. गण. और वियतनाम
7.	कनाडा	कोरोजीन-रेसिस्टेंट स्टील उत्पाद	पाटनरोधी	चीन जन. गण.
8.	यूरोपीय संघ	ऑर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पाद	पाटनरोधी	चीन जन. गण.
9.	यूरोपीय संघ	ऑर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पाद	प्रतिकारी	चीन जन. गण.
10.	यूरोपीय संघ	कोरोजीन रेसिस्टेंट स्टील	पाटनरोधी	चीन जन. गण.
11.	इंडोनेशिया	कोटेड स्टील	पाटनरोधी	चीन जन. गण.
12.	पाकिस्तान	कलर कोटेड स्टील कॉइल्स/शीट्स	पाटनरोधी	चीन जन. गण.
13.	चीनी तैपई	जिंक और जिंक-अलॉयज वाले प्लेटेड और कोटेड फ्लैट रोलड स्टील उत्पाद	प्रतिकारी	चीन जन. गण.

क्रम सं.	आयातक देश	उत्पाद का विवरण	उपाय का प्रकार	देश/देशों की जांच की गई
14.	थाईलैंड	कोल्ड-रोल्ड स्टील के एल्युमीनियम-जिंक अलॉयज वाले प्लेटेड और कोटेड पेंटेड हॉट डिप	पाटनरोधी	चीन जन. गण.
15.	तुर्की	पेंटेड गेल्वेनाइज्ड शीट मेटल (कोल्ड रोल्ड)	पाटनरोधी	चीन जन. गण.
16.	यूक्रेन	कोरोजिन रेसिस्टेंट कोटिंग वाले रोल्ड उत्पाद	पाटनरोधी	चीन जन. गण.
17.	वियतनाम	फ्लैट रोल्ड आयरन अथवा नॉन-अलॉय स्टील, पेंटेड,, प्लेटेड अथवा कोटेड	पाटनरोधी	चीन जन. गण.
18.	जीसीसी	फ्लैट रोल्ड स्टील	रक्षोपाय	यूरोपीय संघ
19.	दक्षिण अफ्रीका	कुछ फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद	रक्षोपाय	स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी

त. यदि मौजूदा उपाय नहीं लगाए जाते हैं, तो भारत बिना किसी व्यापार उपचारात्मक उपायों के संबद्ध देशों के लिए एकमात्र प्रमुख निर्यात स्थल होगा।

थ. वित्त मंत्रालय ने 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 2/2021-सीमा शुल्क के माध्यम से भारत में संबद्ध सामानों के आयातों पर मूल सीमा शुल्क (एमएफएन दर) को 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया है। मूल सीमा शुल्क में इस कमी से चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ से संबद्ध सामानों के आयातों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

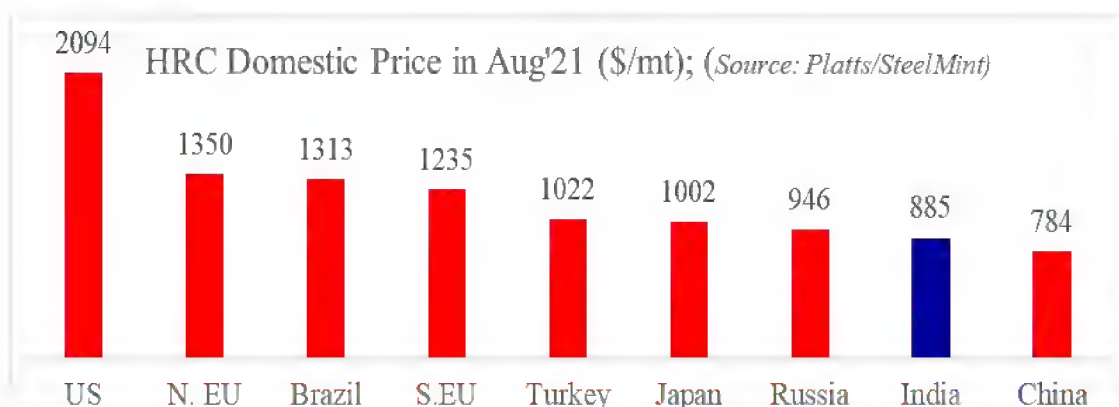
द. संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क 11 जनवरी, 2017 से लगाया गया था। संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद, 2017-18 से आगे भारत में एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पादों के आयातों में काफी वृद्धि हुई है।

एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पाद	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	अक्टूबर, 2017 से सितंबर, 2018
चीन, वियतनाम और कोरिया से कुल आयात	मी. टन	18,220	34,721	1,45,805	2,09,676

स्रोत: अंतिम जांच परिणाम - 21 फरवरी 2020 - एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पादों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

ध. एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पादों का आयात 2017-18 में बढ़कर 1,45,805 मीट्रिक टन और अक्टूबर, 2017 से सितंबर, 2018 की अवधि में 2,09,676 मीट्रिक टन हो गया। एल्युमिनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पाद एक अंतिम चरण का उत्पाद है और इसका उपयोग विचाराधीन उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से, आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने पाटन कीमतों पर एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पादों का आयात करना शुरू कर दिया और भारत में पेंटिंग/रंग कोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी। एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जांच शुरू की गई थी और प्राधिकारी द्वारा उनके आयात पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश 21 फरवरी, 2020 के अंतिम जांच परिणामों के माध्यम से की गई थी, जिसे 23 जून, 2020 को लागू किया गया था। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क जारी नहीं रखा जाता है, तो एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट स्टील उत्पादों के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क अनावश्यक हो जाएगा क्योंकि आयातक/प्रयोक्ता फिर से बड़ी हुई मात्रा में संबद्ध सामानों के आयातों में चले जाएंगे।

- न. प्राधिकारी ने 14 सितंबर, 2021 के अंतिम जांच परिणामों के माध्यम से हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों और कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की है। घरेलू स्तर पर निर्मित हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों के पर्याप्त हिस्से का उपयोग संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए किया जाता है। यदि संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क जारी नहीं रखा जाता है, तो यह हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को कमजोर करेगा।
- प. विचाराधीन उत्पाद फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पादों की मूल्य श्रृंखला में अंतिम उत्पाद है। यदि फ्लैट रोल्ड स्टील श्रेणी में इस अंतिम चरण के तैयार उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क जारी नहीं रखा जाता है, तो अन्य फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क का पूर्ण उपचारात्मक प्रभाव हासिल नहीं होगा।
- फ. भारत सरकार उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के माध्यम से कलर कोटेड स्टील उत्पादों जैसे विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। भारतीय घरेलू उत्पादकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के लिए पर्याप्त निवेश पहले से ही चल रहे हैं।
- ब. संबद्ध सामान भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे संस्कारण प्रतिरोधी गुणधर्म प्रदान करते हैं। जंग के कारण भारत हर साल 5-7% जीडीपी खो देता है।
- भ. वैश्विक उछाल के बावजूद भारत में घरेलू स्टील की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्टील की कीमतों से कम रही हैं जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:



- म. स्टील की कीमतें प्रकृति में चक्रीय हैं। 2008 में हॉट रोल्ड/कोल्ड रोल्ड स्टील की कीमतें अधिक थीं और मौजूदा स्तर के समान थीं। 2009 में, कीमतों में अचानक गिरावट आई और कीमतों में लगभग 65% की कमी आई। दिसंबर 2015 में स्टील की कीमतें गिर गईं और अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गईं। 2014 की तुलना में इस अवधि के दौरान कीमतों में लगभग 52% की गिरावट आई और यह तब हुआ जब भारत में घरेलू उत्पादकों ने भारत सरकार से विभिन्न स्टील उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया। नीचे दिया गया चार्ट स्पष्ट रूप से इस्पात बाजार की दुर्दशा दर्शाता है:



कक. कीमतों की ऐतिहासिक प्रवृत्ति से पता चलता है कि कीमतों में गिरावट 3 से 4 तिमाहियों के भीतर अचानक होती है और उस समय प्रतिक्रिया देने एवं व्यापार उपचारात्मक उपायों की मांग करने का समय नहीं होता है। 2015 में, जब स्टील की कीमतें गिर गईं, तो कई स्टील कंपनियां दिवालिया और परिसमापन की कार्यवाही में चली गईं क्योंकि वे कम कीमतों के हमले को बनाए रखने में सक्षम नहीं थीं। परिसमापन में जाने वाली कंपनियों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- खख. एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। भारत में इस्पात उद्योग सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% है और पर्याप्त प्रत्यक्ष (लगभग 5 लाख) और अप्रत्यक्ष रोजगार (लगभग 20 लाख) सृजित करता है।

गग. घरेलू उद्योग परिवहन सेवाओं, बंदरगाह सुविधाओं, विद्युत आपूर्ति और अन्य आपूर्ति-शृंखला संबंधी क्रियाकलापों जैसी विभिन्न प्रकार की संबद्ध निचले स्तर की सेवाओं की सहायता समर्थन करता है। स्टील उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव इन निचले स्तर के उद्योगों पर भी महसूस किया जाएगा।

घघ. भारत में संबद्ध सामानों के कई उत्पादक हैं और भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों के लिए एकाधिकार या अल्पाधिकार की स्थिति नहीं बनेगी:

- आर्सेलर मित्तल निप्पांन स्टील इंडिया लिमिटेड (पूर्व में एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड)
- जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड
- टाटा ब्लूस्कोप स्टील प्राइवेट लिमिटेड
- टाटा बीएसएल
- भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड
- नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड
- उत्तम गाल्वा स्टील्स लिमिटेड
- इंडियन स्टील कारपोरेशन
- ला टिम मेटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- मानकसिया स्टील्स लिमिटेड
- जिंदल (इंडिया) लिमिटेड
- कलरशाइन कोटेड प्रा. लिमिटेड
- प्रभात ग्लोबल कलर कोटेड प्रा. लिमिटेड
- कलर रूफ (इंडिया) लिमिटेड
- राल्को स्टील्स प्रा. लिमिटेड

डड. वर्तमान संदर्भ कीमत रूप में पाटनरोधी शुल्क का जनहित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि क्षति जांच अवधि के दौरान कोई शुल्क वसूल नहीं किया गया था। हम समझते हैं कि आयातकों अथवा प्रयोक्ताओं द्वारा संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध सामानों के आयात पर किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि आयात संदर्भ कीमत से अधिक कीमत पर किए गए थे। तथापि, निर्धारित/यथामूल्य शुल्क की मौजूदगी को मानते हुए, घरेलू उद्योग सफेद सामानों में प्रयोक्ता उद्योग और अंतिम उपभोक्ताओं पर शुल्क के नगण्य प्रभाव को दर्शाने के लिए निम्नलिखित उदाहरण भी दे रहा है।

उदाहरण 1: रेफ्रीजरेटर

रेफ्रीजरेटर की कीमत	20,000 रुपये
प्रति मी. टन कलर कोटेड की अनुमानित कीमत	100,000 रुपये
20% की दर से लिया गया पाटनरोधी शुल्क	20,000 रुपये
रेफ्रीजरेटर में प्रयुक्त कलर कोटेड स्टील	***
प्रति रेफ्रीजरेटर पाटनरोधी शुल्क-प्रभाव	0-2%

उदाहरण 2: वाशिंग मशीन

वाशिंग मशीन की कीमत	Rs. 15,000
---------------------	------------

प्रति मी. टन कलर कोटेड की अनुमानित कीमत	Rs. 100,000
20% की दर से लिया गया पाटनरोधी शुल्क	Rs. 20,000
वाशिंग मशीन में प्रयुक्त कलर कोटेड स्टील	***
प्रति वाशिंग मशीन पाटनरोधी शुल्क-प्रभाव	0-2%

उदाहरण 3: एयर कंडीशनर

एयर कंडीशनर की कीमत	Rs. 30,000
प्रति मी. टन कलर कोटेड की अनुमानित कीमत	Rs. 100,000
20% की दर से लिया गया पाटनरोधी शुल्क	Rs. 20,000
एयर कंडीशनर में प्रयुक्त कलर कोटेड स्टील	***
प्रति एयर कंडीशनर पाटनरोधी शुल्क-प्रभाव	0-2%

उदाहरण 4: माइक्रोवेव ओवन

माइक्रोवेव ओवन की कीमत	Rs. 9000
प्रति मी. टन कलर कोटेड की अनुमानित कीमत	Rs. 100,000
20% की दर से लिया गया पाटनरोधी शुल्क	Rs. 20,000
माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त कलर कोटेड स्टील	***
प्रति माइक्रोवेव ओवन पाटनरोधी शुल्क-प्रभाव	0-2%

चच. जैसा कि उपर्युक्त तालिकाओं से सिद्ध है, सफेद सामानों के मामले में अंतिम उत्पाद पर 20% पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 1% या 1% से कम है।

व.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

87. निर्णायक समीक्षा जांच के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. संबद्ध देशों से आयातों में काफी कमी आई है क्योंकि उपाय लागू किए गए थे और यूरोपीय संघ के निर्यात क्षति अवधि के दौरान 1% से कम बाजार हिस्सा दर्शाते हैं।
- ख. यूरोपीय संघ की कीमतें चीनी कीमतों से 13% अधिक हैं और भारत में आयातों की औसत कीमत से 59% अधिक हैं।
- ग. उपाय प्रभावी रहे हैं क्योंकि आयात में काफी कमी आई है और घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग काफी अच्छी स्थिति में है। संबद्ध देशों से आयातों में उल्लेखनीय कमी के कारण घरेलू बिक्री में प्रतिभागी घरेलू उत्पादकों की 41% तक और भारत में कलर कोटेड स्टील के अन्य सभी उत्पादकों द्वारा 34% तक वृद्धि हुई है। मांग में 14 सूचकांक तक वृद्धि हुई है। घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा 30-35% से बढ़कर 45-55% हो गया है। क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। लाभप्रदता में 31 सूचकांक

तक वृद्धि हुई है; नकद लाभ में 31 सूचकांक तक वृद्धि हुई है और उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग अपने बिक्री कीमत में 11 सूचकांक तक वृद्धि करने में सक्षम रहा है।

- घ. घरेलू उद्योग की इस स्थिति को देखते हुए, यह तर्क देना बहुत कठिन है कि क्षति के बार-बार होने की संभावना है। यदि भविष्य में घरेलू उद्योग को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो यह यूरोपीय संघ के निर्यात के कारण नहीं होगा, क्योंकि उनके पाटित होने की संभावना नहीं है और मात्रा में काफी वृद्धि होने की संभावना नहीं है।
- ङ. आवेदक ने माईस्टील नेटवर्क रिपोर्ट पर अपने निष्कर्ष को गलत तरीके से आधार बनाया है जो केवल चीनी स्टील बाजार पर ही जोर दे रहा है और इसलिए यूरोपीय संघ के निर्यात के विकास को अपर्याप्त रूप से आंका गया है।
- च. आवेदक अनुचित रूप से दावा करते हैं कि संबद्ध देशों के पास अत्यधिक क्षमताएं और सीमित मांग है तथा इसलिए भारत में आयातों का प्रवाह नहीं बनाने के लिए पाटनरोधी शुल्कों को बढ़ाया जाना चाहिए। तथापि, यूरोपीय संघ में अतिरिक्त क्षमता का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।
- छ. जहां तक कोविड-19 महामारी का संबंध है, यह याद किया जाता है कि इसने दुनिया भर में संबंधित उत्पाद के उत्पादकों को प्रभावित किया है और यह स्थिति भारतीय बाजार के लिए विशिष्ट नहीं है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने भी पुष्टि की कि इस क्षेत्र पर कोरोनावायरस महामारी का प्रभाव पहले की तुलना में कम रहा।
- ज. वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार, 2021 में स्टील की मांग में 5.8% तक वृद्धि होगी और 2022 में 2.7% तक और वृद्धि होगी। यह देखते हुए कि यूरोपीय संघ में, 2021 और 2022 में वसूली अच्छी होने की उम्मीद है, सभी इस्पात प्रयोक्ता क्षेत्रों, विशेष रूप से ऑटोमोटिव और सार्वजनिक निर्माण पहलों में वसूली से संचालित स्थिति में यूरोपीय संघ में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध क्षमता नहीं है जो धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौटने के बाद भारत को निर्यात सृजित करेगी।
- झ. पाटन का परिकलन त्रुटिपूर्ण है क्योंकि आवेदकों ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि भारत अथवा किसी अन्य तीसरे देश को निर्यात किए जाने पर यूरोपीय संघ की कीमतें पाटित की जाती हैं, अथवा यह कि भविष्य में यूरोपीय संघ के निर्यात को पाटित किया जाएगा।

ब.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

88. वर्तमान जांच चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के तहत, प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या मौजूदा शुल्क की समामि से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
89. इस तरह के संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II का खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ, उन कारकों का प्रावधान है जो क्षति के खतरे के लिए संगत हैं और उन्हीं कारकों का प्रयोग निर्णायक समीक्षा में संभावना विश्लेषण के लिए भी किया जा सकता है:

(क) पर्याप्त रूप से बड़े हुए आयात की संभावना दर्शाने वाले भारत में पाटित आयातों की काफी वृद्धि दर।

(ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी हासमान अथवा न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक आयातों के लिए मांग बढ़ने की संभावना होगी तथा

(घ) उस वस्तु की मालसूची जिसकी जांच की जा रही है।"

90. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में सूचीबद्ध कारकों की जांच उपयुक्त आवश्यक सीमा तक की है और अन्य संगत कारकों की भी जांच की है, जिनका घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामस्वरूप क्षति बार-बार होने की संभावना पर प्रभाव हो सकता है।

91. थाई ऐक्रेलिक फाइबर कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में, माननीय सेसटेट ने ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है, क्षति की संभावना की जांच के संबंध में निम्नानुसार टिप्पणी की:

"क्षति के निर्धारण के संबंध में, यदि पाटनरोधी शुल्क का वांछित प्रभाव पड़ा है, तो घरेलू उद्योग की स्थिति में उस अवधि के दौरान सुधार की उम्मीद की जाएगी जब पाटनरोधी शुल्क प्रभावी था। अतः, यह आकलन कि क्या क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी, पाटित आयातों के अनुमानित स्तरों, कीमतों और घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव के आधार पर भविष्य की घटनाओं का प्रति-तथ्यात्मक विश्लेषण आवश्यक होगा। इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस प्रश्न का समाधान करना है कि यदि शुल्क हटाए जाते हैं तो क्या घरेलू उद्योग को फिर से वास्तविक रूप से क्षति होने की संभावना है।"

92. बोरेक्स मोराजी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में, माननीय अधिकरण ने नोट किया कि:

"अभिव्यक्ति 'बार-बार होने की संभावना' अपनी तह की स्थिति के भीतर ले जाएगी जहां पाटन और क्षति पाटनरोधी शुल्क लगाने और जारी रखने के कारण समीक्षा के समय मौजूद न हो, पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभाव समाप्त होने की अनुमति दी जाती है, तो उससे पाटन और क्षति बार-बार होने की संभावना है।"

93. विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय निकाय ने यूएस-संधारण-प्रतिरोधी स्टील निर्णायक समीक्षा (जापान) [डीएस 244] में नोट किया है कि किसी निर्णायक समीक्षा जांच में निर्धारण एक संभावित जांच है, जहां प्राधिकारियों को एक दूरदेशी विश्लेषण करना चाहिए और मुद्दे को हल करने की तलाश करनी चाहिए। यदि शुल्क समाप्त कर दिया गया तो क्या उसके बार-बार होने की संभावना होगी। अपीलीय निकाय ने नोट किया:

"105. यह अपील इन शर्तों में से दूसरी के संबंध में जांच प्राधिकारियों पर लागू होने वाले दायित्वों से संबंधित है। यह उन विशेष विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है जिनमें प्राधिकारियों को अनुच्छेद 11.3 के अनुसार यह निर्धारित करने में अनुपालन करना चाहिए, "कि शुल्क की समाप्ति से पाटन जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना होगी"। इस रिपोर्ट में, हम इस निर्धारण को "संभावना निर्धारण" के रूप में उल्लिखित करते हैं। संभावना निर्धारण एक संभावित निर्धारण है। दूसरे शब्दों में, प्राधिकारियों को एक दूरदेशी विश्लेषण करना चाहिए और इस

मुद्दे को हल करने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर शुल्क समाम कर दिया गया तो क्या उसके होने की संभावना है। ”

94. इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को वर्तमान में क्षति न होने पर, प्राधिकारी के लिए शुल्क की समामि की स्थिति में क्षति के बार-बार होने की संभावना की जांच करने की अपेक्षा है।
95. संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों की भागीदारी के अभाव में, प्राधिकारी ने संभावित विश्लेषण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास किया है।

क. पर्याप्त मात्रा में जारी आयात

96. क्षति जांच अवधि के दौरान आयातों की मात्रा इस प्रकार है:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)	जांच की अवधि
कुल आयात	मी. टन	4,55,776	1,44,139	1,61,650	1,76,289	2,64,434
क) संबद्ध देश	मी. टन	2,58,098	71,610	78,531	70,137	1,05,206
चीन जन. गण.	मी. टन	2,54,954	71,088	76,712	69,353	1,04,029
यूरोपीय संघ	मी. टन	3,145	522	1,819	785	1,177
ख) अन्य देश	मी. टन	1,97,677	72,529	83,119	1,06,152	1,59,228

97. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयात पूर्ण दृष्टि से और भारत में कुल आयात और पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी भारतीय मांग के संबंध में काफी बने हुए हैं।

ख. संबद्ध देशों से पाटन जारी रहना

98. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध सामानों को भारत में पाटित करना जारी रख रहे हैं।

ग. चीन जन. गण. में अधिशेष क्षमता

99. यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस विषयगत निर्णायक समीक्षा में भाग नहीं लिया है। इसलिए, चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर प्राधिकारी के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
100. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों की कुल उत्पादन क्षमता के संबंध में माईस्टील नेटवर्क रिपोर्ट से नवीनतम उपलब्ध सूचना पर विश्वास किया है:

क्रम सं.	विवरण	स्रोत	मिलियन टन
क	चीन जन. गण. की घरेलू मांग	माईस्टील रिपोर्ट	13.50
ख	चीन जन. गण. से कुल निर्यात	माईस्टील रिपोर्ट	6.57

ग	कुल उत्पादन	क+ख	20.07
घ	क्षमता उपयोग	माईस्टील रिपोर्ट	64.54%
ङ	उत्पादन क्षमता	ग/घ	31.10
च	बेकार क्षमता	ङ-ग	11.03

101. प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों की मांग के लिए जेपीसी रिपोर्ट पर विश्वास किया है। विवरण नीचे दिया गया है:

मांग (मी. टन)	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि (वार्षिक)	जांच की अवधि (अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2021)
	18,99,000	18,93,000	23,13,000	21,56,667	32,35,000

102. यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. में उपलब्ध अधिशेष क्षमता भारत में संबद्ध सामानों की कुल वार्षिक मांग के पांच गुना से अधिक है। इसके अतिरिक्त, ऐसे कोई घटक नहीं पाए गए जो यह संकेत दे सकें कि चीन जन. गण. अथवा अन्य तीसरे देश के बाजारों में घरेलू मांग उपलब्ध अधिशेष क्षमता को खपा सकते हैं।

घ. यूरोपीय संघ में अधिशेष क्षमता

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने विषयगत निर्णायक समीक्षा में भाग नहीं लिया है। इसलिए, यूरोपीय संघ के उत्पादकों/निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर प्राधिकारी के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ में संबद्ध सामानों की उत्पादन क्षमता, मांग और अतिरिक्त क्षमता के संबंध में भी कोई विवरण नहीं दिया है।

104. यूरोपीय संघ में संबद्ध सामानों की मांग निम्नानुसार है:

मिलियन टन	2017	2018	2019	2020
मांग*	5.32	5.25	5.54	5.25

स्रोत: यूरोफर और आईएसएसबी * यूरोपीय संघ के उत्पादन, आयात और निर्यात के आधार पर लिया गया

105. यह देखा जाता है कि यूरोपीय संघ में मांग स्थिर है।

106. यूरोपीय संघ में संबद्ध सामानों के उत्पादन आंकड़े और क्षमता नीचे दर्शाई गई है:

	उत्पादन (मिलियन टन)	
वर्ष	यूरोफर के अनुसार	यूरोपीय संघ के विनियम के अनुसार - समाप्ति समीक्षा के बाद चीन जन. गण. के मूल के कुछ ऑर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति समीक्षा
2014	4.57	4.40
2015	4.58	4.40
2016	4.87	4.76
2017	4.94	4.75

2018	4.93	उपलब्ध नहीं
2019	5.14	उपलब्ध नहीं
2020	5.03	उपलब्ध नहीं

107. यह देखा जाता है कि 2014 से 2018 के लिए यूरोफर से यूरोपीय संघ के उत्पादन आंकड़े चीन जन. गण. के मूल के कुछ ऑर्गेनिक कोटेड स्टील उत्पादों के आयातों से संबंधित 2 मई, 2019 के अंतिम जांच परिणाम में उत्पादन आंकड़ों से तुलनीय है। चूंकि 2 मई, 2019 के यूरोपीय आयोग के जांच परिणाम में नवीनतम अवधि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अतः यूरोपीय संघ का उत्पादन और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए 2018 से 2020 के लिए यूरोफर से प्राप्त आंकड़ों पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय आयोग के दिनांक 2 मई, 2019 के जांच परिणाम के अनुसार, यूरोपीय संघ के इस्पात उद्योग का क्षमता उपयोग सुसंगत रहा है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लेख किया गया है:

विवरण	2014	2015	2016	2017	औसत
उत्पादन (मी. टन)	44,02,079	44,04,178	47,69,698	47,52,003	45,81,990
क्षमता (मी. टन)	50,76,892	51,13,417	53,61,693	53,39,200	52,22,801
उपयोग (%)	87%	86%	89%	89%	88%

109. इस प्रकार, वर्ष 2020 के उत्पादन और 88% की औसत क्षमता उपयोग के आधार पर, यूरोपीय संघ की क्षमता निकाली गई है। यूरोपीय संघ के निपटान में अतिरिक्त क्षमता नीचे दी गई है:

मिलियन टन	स्रोत	2018	2019	2020
उत्पादन (ग)	यूरोफर	4.93	5.14	5.03
आयात	आईएसएसबी	0.94	1.00	0.83
निर्यात	आईएसएसबी	0.62	0.61	0.61
मांग (क)	ली गई	5.25	5.54	5.25
क्षमता (ख)	ली गई	5.60	5.84	5.72
मांग की अधिक क्षमता (ख) - (क)	ली गई	0.35	0.30	0.47
उत्पादन की अधिक क्षमता (ख) - (ग)	ली गई	0.67	0.70	0.69

110. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ के पास 2020 में कम से कम 4,70,000 मीट्रिक टन की मांग की अधिक क्षमता है। उत्पादन की अधिक क्षमता 2020 में 6,90,000 मीट्रिक टन है। यूरोपीय संघ अधिशेष क्षमता कुल मांग से अधिक भारतीय मांग के लगभग 22% है और यूरोपीय संघ में अधिशेष क्षमता कुल उत्पादन से अधिक भारतीय मांग के लगभग 32% है।

रिकॉर्ड में निर्दलीय रिपोर्ट इस प्रकार इंगित करती है कि संबद्ध देशों के पास भारी अधिशेष क्षमताएं उपलब्ध हैं।

ड. अन्य देशों द्वारा व्यापार उपचारात्मक उपाय

111. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में अन्य देशों द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के विरुद्ध अनेक व्यापार उपचारात्मक उपाय लगाए गए हैं।

112. प्राधिकारी माईस्टील नेटवर्क रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं जिसमें उल्लेख किया गया है कि चीन जन. गण. से कलर कोटेड प्लेटों और काँइल के आयातों के संबंध में लगभग 20 व्यापार उपचारात्मक जांचें चल रही हैं।
113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए पर्याप्त उत्पादन वाले लगभग सभी देशों ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के विरुद्ध व्यापार उपचारात्मक उपाय लगाए हैं।

च. कीमत आकर्षकता

114. चीनी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता के संबंध में सूचना नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विचाराधीन उत्पाद	यूनिट	2018	2019	2020
एफओबी निर्यात कीमत (विश्व)	अमरीकी डॉलर/मी. टन	826	737	717

स्रोत: आईएसएसबी आंकड़े

विचाराधीन उत्पाद	यूनिट	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
भारत में आयात कीमतें	अमरीकी डॉलर/मी. टन	861	772	801

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस आंकड़े

115. यह देखा जा सकता है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा तीसरे देशों को संबद्ध सामानों का निर्यात भारत को निर्यात कीमत से कम कीमतों पर है। इस प्रकार, भारतीय बाजार चीन जन. गण. के निर्यातकों/उत्पादकों के लिए कीमत आकर्षक है।

छ. पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर तीसरे देशों को निर्यात

116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के निर्यात के संबंध में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि चीन जन. गण. से तीसरे देशों को किए गए अधिकतर निर्यात पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर हैं।

विवरण	यूनिट	पाटन मार्जिन	क्षति मार्जिन	कीमत कटौती
जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के कुल निर्यात	मी. टन	***	***	***
सकारात्मक पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन/कीमत कटौती वाले निर्यात	मी. टन	***	***	***
सकारात्मक पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन/कीमत कटौती वाले निर्यात	%	95%	38%	78%

स्रोत: आईएसएसबी आंकड़े

117. यह देखा जाता है कि चीन जन. गण. से तीसरे देशों को विचाराधीन उत्पाद के लगभग सभी निर्यात पाटित कीमतों पर हैं। इसके अतिरिक्त, चीन जन. गण. से तीसरे देशों को विचाराधीन उत्पाद का 38% निर्यात घरेलू

उद्योग के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमतों से कम कीमतों पर है और चीन जन. गण. से तीसरे देशों को विचाराधीन उत्पाद के 78 प्रतिशत निर्यात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमतों पर हैं।

118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ द्वारा तीसरे देशों को विचाराधीन उत्पाद के 29 प्रतिशत निर्यात पाटित कीमतों पर हैं।

जांच की अवधि के दौरान यूरोपीय संघ से तीसरे देशों के निर्यात

विवरण	यूनिट	पाटन मार्जिन
यूरोपीय संघ से कुल निर्यात	मी. टन	***
सकारात्मक पाटन मार्जिन की मात्रा	मी. टन	***
सकारात्मक पाटन मार्जिन की मात्रा	%	29%

स्रोत: आईएसएसबी

ज. संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन

119. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क 11 जनवरी 2017 से लगाया गया था। संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद, 2017-18 से आगे भारत में एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पादों के आयातों में काफी वृद्धि हुई है।

एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पाद	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	अक्टूबर, 2017 से सितंबर, 2018
चीन, वियतनाम और कोरिया से कुल आयात	मी. टन	18,220	34,721	1,45,805	2,09,676

स्रोत: अंतिम जांच परिणाम - 21 फरवरी 2020 - एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पादों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

120. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद, एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पादों के आयात 2017-18 में बढ़कर 1,45,805 मीट्रिक टन और अक्टूबर, 2017 से सितंबर, 2018 में 2,09,676 मीट्रिक टन हो गये। एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पाद एक अंतिम चरण का उत्पाद है और इसका उपयोग विचाराधीन उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से, आयातकों/प्रयोक्ताओं ने पाटित कीमतों पर एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पादों का आयात करना शुरू कर दिया और भारत में पेंटिंग/कलर कोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी। कलरिंग/पेंटिंग लाइन की स्थापना के लिए आवश्यक निवेश नगण्य है।
121. एल्युमीनियम और जिंक कोटेड फ्लैट उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जांच शुरू की गई थी और प्राधिकारी द्वारा उनके आयात पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश 21 फरवरी, 2020 के अंतिम जांच परिणामों द्वारा की गई थी, जिसे 23 जून, 2020 को लागू किया गया था।
- झ. हॉट रोलड और कोल्ड रोलड स्टील उत्पादों पर दिया गया संरक्षण
122. प्राधिकारी ने 14 सितंबर, 2021 के अंतिम जांच परिणामों द्वारा हॉट रोलड फ्लैट स्टील उत्पादों और कोल्ड रोलड फ्लैट स्टील उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की है। घरेलू रूप से निर्मित हॉट रोलड और कोल्ड रोलड फ्लैट स्टील उत्पादों के काफी भाग का उपयोग संबद्ध सामानों का उत्पादन में किया जाता है।

ज. स्टील की कीमतों की चक्रीय प्रकृति

123. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस्पात की कीमतें प्रकृति में चक्रीय हैं और पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक अस्थिर बनी हुई हैं। कीमतें महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अधीन होती हैं जिनमें कीमतें कुछ निश्चित अवधियों में ऊपर जाती हैं और उसके बाद कीमतों में विघटन होते हैं।

ट. प्रकटीकरण के उपरांत टिप्पणी

घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत किए गए अनुरोध

124. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार आया है तथापि, ऐसी स्पष्ट संभावना है कि यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों को हटा लिया जाता है, तो घरेलू उद्योग को क्षति की भी पुनरावृत्ति हागी।
- ख. क्षमता उद्योग में गिरावट आई है, लेकिन जांच की अवधि (क) में क्षमता उपयोग में गिरावट, केवल क्षमता में वृद्धि के कारण से ही नहीं है। क्षमता उपयोग में गिरावट भी आवेदक घरेलू घरेलू उद्योग द्वारा विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि (क) में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में कमी आने के कारण से है।
- ग. जांच की अवधि में क्षमता उपयोग कम है और घरेलू उद्योग, यदि ईष्टतम क्षमता उपयोग पर प्रचालन करता है तो घरेलू मांग की अधिकांश हिस्से को पूरा कर सकता है।
- घ. कीमत कटौती के संबंध में यह नोट किया जाता है कि चीन जन.गण. से कीमत कटौती कुछ सकारात्मक है। यह दर्शाता है कि चीन जन.गण. से आयात घरेलू उद्योग की बिक्रियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और उनसे घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी कटौती हो रही है।
- ङ. समग्र कीमत कटौती, वास्तविक आयात कीमत को नहीं दर्शाती क्योंकि चीन जन.गण. और यूरोपीय संघ से जांच की अवधि में आयातों में पर्याप्त कीमत संबंधी अंतर है। घरेलू उद्योग की बिक्रियों पर भी कम कीमत के आयातों के कारण प्रभाव पड़ा है, जिनसे घरेलू उद्योग को मेल रखने की संभावना है।
- च. नकारात्मक क्षति मार्जिन को पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारक नहीं कहा जा सकता। संबद्ध देशों से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने भाग नहीं लिया है और इसीलिए प्राधिकारी निर्यात कीमत और संबद्ध देशों में प्रत्येक व्यक्तिगत उत्पादक/निर्यातक के क्षति मार्जिन की पुष्टि करने में असमर्थ हैं। डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के आधार पर औसत आयात कीमत सही हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है।
- छ. संबद्ध देशों से जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक है और इसीलिए नकारात्मक क्षति मार्जिन पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत के लिए आकलन करने हेतु भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।
- ज. एक निर्णायक समीक्षा में विचारार्थ प्राथमिक तत्व, पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की मौजूदगी होना है। अतः जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक क्षति मार्जिन, घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना का आकलन करने के लिए निर्धारक नहीं है।
- झ. स्टील की कीमतों की चक्रीय प्रकृति पर विचार करते हुए विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतें, एक कर कीमतें पीक पर पहुंच जाने के बाद अल्प समय में गिरने की संभावना होती है। यदि कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है तो घरेलू उद्योग पर कम कीमतों पर आयातों से प्रभाव पड़ेगा, जो भविष्य में मौजूद रहने की संभावना है।
- ञ. यदि एक निर्णायक समीक्षा जांच में यह स्थापित हो जाता है कि पाटन और क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, प्राधिकारी को इस तथ्य के बावजूद कि क्षति मार्जिन नकारात्मक है, पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की जरूरत है। निम्नलिखित निर्णायक समीक्षा जांचों में प्राधिकारी के विगत के अंतिम जांच परिणामों पर भरोसा किया गया है :-

- 2100 एमएम तक की चौड़ाई और 25 एमएम तक की मोटाई के कॉइल में अलॉय अथवा नॉन-अलाय स्टील के हॉट रोल्ड उत्पाद
 - सभी चौड़ाई और मोटाई वाले आयात अथवा नान अलाय स्टील अथवा अन्य अलाय स्टील के कोल्ड रोल्ड/कोल्ड रिज्यूस्ड फ्लैट स्टील उत्पाद- क्लेड, प्लेटेड अथवा कोटेड नहीं।
 - यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 2 इथाइल हेक्सानोल- फा. सं. 7/28/2020-डीजीटीआर दिनांक 8 मार्च, 2021,।
 - चीन जन गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “नाइलोन टायर कोर्ड फैब्रिक” – फा. सं. 7/22/2019-डीजीटीआर दिनांक 29 अक्टूबर, 2020
 - कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब और ताइवान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित “एसिटोन” फा.सं. 07/09/2019-डीजीटीआर दिनांक 29 सितंबर, 2020
 - चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए “फ्रंट एक्सल बीम” और “स्टीयरिंग नकल” 07/26/2020-डीजीटीआर दिनांक 24 दिसंबर, 2020
 - चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित पार्शियली ओरिएंटेड यार्न (पीओवाई) फा. सं. 15/27/2010-डीजीएडी दिनांक 10 फरवरी, 2012
 - पाकिस्तान, सऊदीअरब और यू ए ई से क्लीयर फ्लोट ग्लास फा. सं. 7/3/2019-डीजीटीआर दिनांक 07/11/2019.
 - चीनी ताइपेई के मूल की अथवा वहां से निर्यातित नोनाइल फिनाइल: फा.सं.15/1007/2012-डीजीएडी दिनांक 08/11/2013.
 - चीन जन.गण., मलेशिया, थाइलैंड, श्रीलंका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित, 6 एमएम या इससे अधिक मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबोड : फा.सं. 7/6/2020-डीजीटीआर दिनांक 08/01/2021.
 - चीन जन.गण. और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित, रबड़ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक: फा.सं. 7/15/2020-डीजीटीआर दिनांक 22/12/2020.
 - चीन जन.गण., थाइलैंड और यूएसए से पीवीसी सस्पेंशन ग्रेड रेसिन : फा.सं. 7/34/2018-डीजीटीआर दिनांक 18/07/2019
- ट. माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ (दिनांक 23 फरवरी, 2017 का आदेश, विशेष सिविल याचिका सं. 16426-16427/2016) में यह कहा है कि नकारात्मक क्षति मार्जिन को इस निर्धारण के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता कि पाटन और/अथवा क्षति की कोई संभावना है।
- ठ. प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कैप्टिव इनपुट के उत्पादन के लिए प्रयुक्त असेट पर नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत की दर से प्रतिफल की अनुमति है। यदि कैप्टिव इनपुट की बाजार कीमत पर एन आई पी के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जाता।
- ड. कलर कोटेड स्टील उत्पाद के लिए निर्धारित एनआईपी कोल्ड रोल्ड स्टील फ्लैट उत्पाद के लिए निर्धारित एनआईपी से अधिक होना चाहिए, क्योंकि कलर कोटेड स्टील एक मूल्यवर्धित उत्पाद है।
- ढ. विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर बुनियादी सीमाशुल्क को दिनांक 1 फरवरी, 2021 से 12.5 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया है, जिससे विदेशी निर्यातकों/भारतीय आयातकों को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात/ आयात करने में लीवरेज दिया गया है।

ट.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए, प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोध

125. प्रकटीकरण विवरण के उत्तर में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं दिया गया है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

126. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों की जांच की है और यह नोट किया है कि अधिकांश टिप्पणियां पुनः की गई हैं, जिनकी पहले ही उपयुक्त जांच की जा चुकी है और इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में उपयुक्त रूप से विचार किया जा चुका है।
127. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मामलों और प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए मामलों की नीचे जांच की गई है।
128. एनआईपी के निर्धारण के लिए अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एन आई पी का निर्धारण, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III और प्राधिकारी की सतत प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।
129. इस अनुरोध के संबंध में कि उत्पादन में गिरावट और क्षमता में वृद्धि के कारण जांच की अवधि (क) में क्षमता उपयोग में गिरावट है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि (क) के दौरान कुछ तो क्षमता में वृद्धि होने के कारण और कुछ में उत्पादन में गिरावट आने के कारण क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
130. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी को क्षति की संभावना और घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार की जांच करनी चाहिए और नकारात्मक क्षति मार्जिन निर्धारक नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने केवल उन्हीं मापदंडों पर भरोसा नहीं किया है बल्कि पाटन और क्षति की संभावना का आकलन करने के लिए संगत समस्त सूचना की जांच की है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि थाई एक्रिलिक फाइबर कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय सेस्टेट ने एक ऐसी स्थिति में, जहां, घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार आया है, क्षति की संभावना की जांच करने के संबंध में यह पाया है कि :-

“क्षति निर्धारण के संबंध में, यदि पाटनरोधी शुल्क का अपेक्षित प्रभाव होता, तो घरेलू उद्योग की स्थिति में ऐसी अवधि के दौरान सुधार हो गया होता, जोकि प्रभावित थी। अतः यह आकलन करना कि क्या क्षति जारी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी, यदि पटित आयातों, कीमतों और घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव के अनुमानित स्तरों के आधार पर भविष्य का एक प्रति-तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाए। इस प्रकार के निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस प्रश्न का समाधान करना है कि क्या घरेलू उद्योग को, यदि शुल्क हटा लिए जाते हैं तो पुनः क्षति होने की संभावना है”

131. इसी प्रकार, बोरेक्स मोरारजी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में, माननीय न्यायाधिकरण ने यह नोट किया है कि :

“यह व्याख्या कि “पुनरावृत्ति होने की संभावना”, इसकी आंतरिक स्थिति में होगी, जहां पर कि पाटन और क्षति, पाटनरोधी शुल्क लगाने और जारी रखने के कारण, समीक्षा के समय मौजूद नहीं भी हो सकती, जिसे यदि पांच वर्षों की समाप्ति पर उसका प्रभाव बंद करने दिया जाता है, तो पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है”

132. प्राधिकारी ने तदनुसार यह जांच कर पाटन और क्षति की संभावना का आकलन किया है कि संबद्ध देशों से पाटन की क्या संभावित स्थिति हो सकती है और घरेलू उद्योग को क्या क्षति हो सकती है। यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने दिया जाता है।

ठ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मामले

133. प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी

रखने से यह व्यापक लोक हित के खिलाफ होगा। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, आयातकों और उत्पाद के प्रयोक्ताओं/उपयोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों और रिकॉर्ड पर सूचना पर विचार किए जाने के आधार पर है।

134. प्राधिकारी ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है, जिसके सभी हितबद्ध पक्षकारों व आयातकों, उपभोक्ताओं/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से, संबद्ध निर्णायक समीक्षा जांच के संबंध में उनके विचार आमंत्रित किए गए हैं। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने जांच में भाग नहीं लिया है और प्राधिकारी के समक्ष ब्यौरे साझा नहीं किए हैं। यहां तक कि प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा के लिए प्रयोक्ताओं के लिए फार्मेट भी निर्धारित किया है और यह स्पष्ट किया है कि कैसे पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह नोट किया है कि किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने जांच में भाग नहीं लिया है और कोई संगत सूचना प्रदान नहीं की है।
135. उत्पाद आसानी से आयात करने योग्य श्रेणी के तहत आता है और इसीलिए यह विभिन्न देशों से आसानी से आयात होता है। पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से, संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करके निर्मित किए गए उत्पाद के कीमत स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है और उसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की प्रतिस्पर्धा पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में, पाटनरोधी उपायों के कारण कमी नहीं आएगी। सामान्यतः पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन, घरेलू उद्योग को, पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया के कारण क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय व्यापार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनर्स्थापना हो सके, जोकि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को जारी रखने से केवल पाटन की प्रक्रियाओं से प्राप्त अनुचित लाभों को दूर किया जाएगा।
136. संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग बहुत से अनुप्रयोगों और शामिल क्षेत्रों में किया जाता है किन्तु यह निर्माण, ऑटोमोटिव, धुलाई की मशीन और फ्रिज, व्हाइट गुड्स, फर्नीचर आदि तक सीमिति नहीं है। पीयूसी अवरोध संरक्षण के साथ जंग के प्रति प्रतिरोध प्रदान करता है। संबद्ध वस्तुओं की जंग प्रतिरोधक विशेषताओं के कारण संबद्ध वस्तुओं का निर्माण क्षेत्र, व्हाइट गुड्स आदि में प्रयोग बढ़ रहा है।
137. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए परिमाणित जानकारी प्रस्तुत की है कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का प्रभाव तैयार उत्पाद पर न्यूनतम होगा। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, यह नोट किया गया है कि पीयूसी पर 20 प्रतिशत @ पर एक पाटनरोधी शुल्क की परिकल्पना करते हुए, उस का प्रभाव केवल गैर-महत्वपूर्ण होगा अर्थात् रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, वाशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन आदि जैसी व्हाइट गुड्स के कुल मूल्य पर 1 प्रतिशत या 1 प्रतिशत से भी कम।
138. घरेलू उद्योग की सूचना दर्शाती है कि घरेलू उद्योग की विनिर्माण सुविधाएं कम प्रयोग की गई हैं और घरेलू मांग के बड़े हिस्से को पूरा करने के लिए इन्हें बढ़ाया जा सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमतों या आयात कीमतों से कम कीमतों की तुलनीय कीमतों पर घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की जा रही है।
139. संदर्भ कीमत-आधारित शुल्क यह सुनिश्चित करेंगे कि विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ता और आयातक विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होंगे अगर भारत में आयात उचित कीमतों पर हैं। संदर्भ कीमत आधारित शुल्क यह भी सुनिश्चित करते हैं कि घरेलू उद्योग भारत में कम कीमतों/अनुचित मूल्य आयात से क्षतिग्रस्त नहीं है। अतः, संदर्भ कीमत-आधारित शुल्क वर्तमान मामले में एक ओर आयातकों और प्रयोक्ताओं के हित और दूसरी ओर घरेलू उद्योग के हित के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करेंगे।
140. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों की एक बड़ी संख्या है और पाटन रोधी शुल्क के जारी रहने के कारण संबद्ध वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार में एकाधिकारवादी या अल्पाधिकारवादी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

141. अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि निकट भविष्य में कीमतें कम हो जाती हैं तो जारी संदर्भ कीमत आधारित शुल्क घरेलू उद्योग के लिए एक सुरक्षा जाल सुनिश्चित करेंगे।

ड. निष्कर्ष

142. उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों, जैसाकि ऊपर रिकॉर्ड किया गया है और घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निष्कर्ष देते हैं कि:

- i. आवेदक घरेलू उत्पादक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है और घरेलू उत्पादकों की ओर से आवेदक द्वारा दायर आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति संबंधी मापदंड को पूरा करता है।
- ii. आवेदन निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के प्रयोजनार्थ सारी संगत सूचना अन्तर्निहित करता है और आवेदन वर्तमान निर्णायक समीक्षा की शुरुआत को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य सम्मिलित करता है।
- iii. प्राधिकारी ने पीओआई के रूप में अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2021 तक की 18 महीनों की लंबी अवधि पर विचार किया है ताकि यह घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही वर्तमान और संभावित पाटन और क्षति में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करा सके। इसके अलावा, कथित पाटित आयातों के कारण उत्पन्न घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति/क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का आकलन करने के लिए वर्तमान निर्णायक समीक्षा में एक दीर्घ पीओआई उचित मानी गई क्योंकि 2020-21 की पहली और न दूसरी तिमाही में व्यापार कोविड-19 से प्रभावित था।
- iv. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, प्रत्येक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है क्योंकि संबद्ध देशों से किसी उत्पादक/निर्यातक ने भाग नहीं लिया है। संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण है। इसलिए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने की संभावना है।
- v. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में, पाटन और क्षति के प्रति असुरक्षित है।
- vi. संभावना संबंधी विश्लेषण आयोजित करने पर प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:-
 - क. जैसाकि रिकॉर्ड पर उपलब्ध स्वतंत्र रिपोर्टों से साक्ष्य है, संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के पास उपलब्ध विचाराधीन उत्पाद की वृहत अतिरिक्त क्षमता है।
 - ख. संबद्ध देशों से तीसरे देशों को निर्यात कीमत के संबंध में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना की जांच दर्शाती है कि पाटित/क्षतिकारक कीमतों पर तीसरे देशों को महत्वपूर्ण निर्यात किए गए हैं।
 - ग. संबद्ध देशों के लिए महत्वपूर्ण उत्पादन आधार वाले अधिकतर देशों ने संबद्ध देशों से कलर कोटिड/प्री-पेंटिड फ्लैट स्टील उत्पादों के आयातों पर व्यापार उपचार उपाय लागू किए हैं और/या जारी रखे हैं। अतः, संबद्ध देशों के पास अतिरिक्त क्षमता का प्रयोग करने और अन्य बाजारों को निर्यात करने के बहुत कम विकल्प उपलब्ध हैं।
 - घ. संबद्ध देशों से तीसरे देशों को निर्यात कीमत के संबंध में रिकॉर्ड पर सूचना की जांच दर्शाती है कि तीसरे देशों को महत्वपूर्ण निर्यात भारत को निर्यात कीमत से कम कीमतों पर किए गए हैं, जो दर्शाता है कि भारतीय बाजार संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अधिक कीमत आकर्षक है।
- vii. प्राधिकारी तदनुसार निष्कर्ष देते हैं कि शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना है।

- viii. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए संदर्भ कीमत आधारित शुल्क सुनिश्चित करेंगे कि जब भारत में उचित कीमत पर आयात किए जाते हैं तो विचाराधीन उत्पाद को प्रयोक्ता और आयातक विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होते।

ढ. सिफारिशें

143. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा आरंभ की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, मार्जिन और कारणात्मक संबंध व पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति के पहलुओं पर सूचना उपलब्ध कराने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। नियमावली के अंतर्गत, निर्धारित उपबंधों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध और पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना को ध्यान में रखते हुए निर्णायक समीक्षा को आरंभ और आयोजित करते हुए, प्राधिकारी का विचार है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण को जारी रखना जरूरी है।
144. तदनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वर्तमान मात्रा और स्वरूप को जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझते हैं। अतः, अधिसूचना सं. 49/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 17 अक्तूबर, 2017 के अनुसार लागू वर्तमान निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना जरूरी समझते हैं। प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करते हैं।
145. पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य और नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में इंगित राशि के बीच के अंतर के रूप में की गई है बशर्ते कि पहुंच मूल्य कॉलम 7 में इंगित मूल्य से कम है। यदि पहुंच मूल्य कॉलम-7 में इंगित मूल्य से अधिक है तो पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य निर्धारणीय मूल्य होगा जैसाकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क के रूप में और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3,3क,8ख,9,9क के तहत उद्धृत शुल्कों के अलावा सीमा शुल्कों के लागू स्तर पर होगा।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7210, 7212, 7225 और 7226	क्वायल्स में अथवा क्वाइल्स में नहीं, प्रीपेंटेड, कलर कोटेड अथवा आर्गेनिक कोटेड फ्लैट स्टील्स, चाहे वह ज़िंक, एल्युमिनियम	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	कोई	822	एमटी	यूएस डॉलर

		जिंक अथवा अन्य किसी सबस्ट्रेट कोटिंग के मैटलिक कोटेड सबस्ट्रेड के साथ हो अथवा नहीं *						
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. और यूरोपीय संघ के अतिरिक्त कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	822	एमटी	यूएस डॉलर
3	-वही-	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई देश	कोई	822	एमटी	यूएस डॉलर
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. और यूरोपीय संघ के अतिरिक्त कोई देश	यूरोपीय संघ	कोई	822	एमटी	यूएस डॉलर

*टिप्पणी: - वस्तुओं के विवरण में 6 मि.मी. या अधिक मोटाई की प्लेट्स शामिल नहीं हैं।

आगे की प्रक्रिया

146. केन्द्रीय सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील, जो इस सिफारिश से उत्पन्न हो सकती है, इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसरण में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2021

FINAL FINDINGS**Case No. AD-(SSR)-14/2021**

Subject: Sunset review anti-dumping investigation concerning imports of “Colour Coated/Pre-painted flat products of alloy or non-alloy steel” originating in or exported from China PR and European Union.

F. No. 7/16/2021-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Anti-Dumping Rules” or “Rules” or “AD Rules”);

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. On 29th June 2016, the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Designated Authority” or the “Authority”) had initiated an investigation to examine the nature and extent of dumping and its injurious effect on the domestic industry with respect to “Colour coated / pre-painted flat products of alloy or non-alloy steel” (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) originating in or exported from China PR and the European Union (hereinafter referred to as “subject countries”). The original petition for imposition of anti-dumping duty was filed by M/s. Essar Steel India Limited and M/s. JSW Steel Coated Products Limited.
2. The Authority issued the preliminary findings on 20th October 2016 vide Notification No. No.14/28/2016-DGAD and recommended imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries in the form of reference price. The Authority issued corrigendum to the aforementioned preliminary findings vide notification dated 30th November 2016. The Central Government imposed the provisional anti-dumping duty on the subject goods on 11th January 2017 vide Notification No. 02/2017-Customs (ADD) for a period of six months.
3. The Authority issued the final findings on 30th August 2017 vide Notification No. 14/28/2017-DGAD and recommended imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries in the form of reference price for five years. On the basis of the aforesaid findings, the Central Government imposed the definitive anti-dumping duty in the form of reference duty vide Notification No. 49/2017-Customs (ADD) dated 17th October 2017 for a period of five years w.e.f. 11th January 2017.
4. In terms of Section 9A (5) of the Act; anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Further, Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

"any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry."
5. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of the anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

6. And whereas, in terms of the above provisions, Indian Steel Association, on behalf of JSW Steel Coated Products Limited and ArcelorMittal Nippon Steel India Limited (erstwhile Essar Steel India Limited) (hereinafter also referred to as the “Applicant” or “Applicant companies” or “domestic industry”) filed an application before the Designated Authority in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules for initiation of sunset review investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries. The request was based on the grounds that the expiry of the measure was likely to result in continuation of dumping of the subject goods and recurrence of material injury to the domestic industry.
7. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the Applicant, the Authority issued a public notice vide Notification No. F. No. 7/16/2021-DGTR dated 26th July 2021, published in the Gazette of India, initiating sunset review investigation on the imports of the product under consideration from China PR and the European Union in accordance with the Anti-Dumping Rules to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
8. The scope of the present review covers all aspects of the Final Findings Notification No. 14/28/2017-DGAD dated 30th August 2017 which had recommended the imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.

B. PROCEDURE

9. The procedure described below has been followed in this sunset review investigation:
 - i. The Authority vide Notification No. 7/16/2021-DGTR dated 26th July 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiated sunset review of anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.
 - ii. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 26th July 2021 to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, the known importers/users and other interested parties, as per the available information. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
 - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of subject countries in India in accordance with the Rule 6(3) of the Rules.
 - iv. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the producers/exporters from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also shared with the Embassies along with the names and addresses of the known producers/exporters from the respective subject countries.
 - v. The Authority sent exporters’ questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with the Rule 6(4) of the Rules to elicit relevant information:
 - a. ThyssenKrupp Steel Europe AG
 - b. Tata Corus
 - c. SSAB
 - d. Metal Trade Comax
 - e. Voestalpine AG
 - f. Shanghai Metal Corporation
 - g. Baosteel Group Corporation
 - h. Sino East Steel Enterprise Co. Ltd
 - i. Qingdao Sino Steel Co. Ltd
 - j. Shanghai Color Steel Co. Ltd

- k. Shandong Hwafone Steel Co. Ltd.
 - l. Jiangsu Shagang International Trade Co. Ltd./ Zhangjiagang Shagang Heavy Plate Co. Ltd / Jiangyin Xingcheng Special Steel Works, Co., Ltd, China PR
 - m. Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co. Ltd
- vi. None of the producers/exporters from the subject countries have filed the exporter's questionnaire response with the Authority in the present sunset review investigation.
 - vii. The Authority forwarded a copy of the notification to the following known importers/consumers/user associations of the subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the prescribed time limit in accordance with the Rule 6(4) of Rules.
 - a. Consumer Electronics and Appliance Manufacturers Association
 - b. Bombay Iron Merchants Association
 - c. Pre-Engineered Structures Society of India
 - d. Sungreen Ventilation Systems Private Limited
 - e. Shree Ram Steel Syndicate
 - f. Indian Pipes Private Limited
 - g. Metal Shine Roofing
 - h. Brijlal & Sons
 - i. Kumar Corporation
 - j. Oriental Metals India Private Limited
 - k. M.K.K Metal Sections Private Limited
 - l. Kusum Metals Private Limited
 - m. Steel Co.
 - n. Shanker Mercantile Private Limited
 - o. GM Traders
 - p. PB Traders Private Limited
 - q. Whirlpool India Limited
 - r. Samsung India Electronics Private Limited
 - viii. None of the importers/consumers/user associations have responded and filed the importer/user questionnaire response. One importer, Shanti Iron Traders, registered itself as an interested party with the Authority but did not file any submission during the course of the review investigation.
 - ix. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st October 2019 to 31st March 2021 (18 months). The injury examination period has been considered as the period 2017-18, 2018-19, 2019-20, and the POI.
 - x. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S import data for computation of the volume & value of imports and for injury analysis.
 - xi. Verification of the information and the data submitted by the domestic industry was carried out to the extent deemed necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of this final findings.
 - xii. The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') as per the cost of production and the cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules has been worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

- xiii. The Authority held an oral hearing on 16th September 2021 to provide an opportunity to the interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6) of the AD Rules. The oral hearing was held through video conferencing in view of the special circumstances arising out of the COVID-19 pandemic. The oral hearing was attended by the domestic industry and the European Commission. The interested parties who attended the oral hearing were requested to file written submissions and rejoinders.
- xiv. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation and the oral hearing, have been addressed in this final finding, to the extent considered relevant by the Authority.
- xv. As no producer/exporter from the subject countries have come forth and filed any submission or questionnaire response, only the information provided by the domestic industry on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed in the public record. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xvi. In accordance with the Rules, the Authority disclosed the essential facts of the case that would form the basis of its findings in the form of a disclosure statement on 30.09.2021 and the interested parties were allowed time up to 4.10.2021 to comment on the same. The comments of the interested parties, to the extent relevant, have been considered by the Authority and have been addressed in this finding.
- xvii. *** in this final finding represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xviii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US \$1= 74.34 INR.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions made by the domestic industry and other interested parties

- 10. Domestic industry or any other interested party has not made any submission with regard to the scope of product under consideration in the present review investigation.

C.2. Examination by the Authority

- 11. The scope of product under consideration in the present sunset review investigation is the same as was decided by the Authority in the final findings of the original investigation dated 30th August 2017.
- 12. The product under consideration is:

“Pre-painted, painted, colour coated or organic coated flat steels in coils or not in coils, whether or not with metallic coated substrate of zinc, aluminium zinc or any other substrate coating excluding plates of thickness 6 mm or more.

These products are either of alloy or non-alloy steel, whether of prime or non-prime quality, either in form of coils or plain sheets or profiled sheets including but not limited to trapezoidal, sinusoidal, corrugated or any other type of profile. These products are available in various paint qualities and a variety of paint colours, whether or not pre-coated with primer or any other suitable material. These products may either be painted on top surface of the steel sheet or on bottom surface or on both top and bottom surfaces. This product may be supplied with or without guard film/lamination.

- 13. The PUC offers resistance to corrosion along with barrier protection. The PUC is used in many applications and sectors including but not limited to construction, roofing, walling, panelling, cladding and decking, automotive, white goods & appliances and furniture etc.
- 14. The PUC is classified under Customs Tariff Headings 72107000, 72124000, 72259900 and 72269990 of the Customs Tariff Act 1975. However, the imports have also been observed in certain other Customs Tariff HS Codes viz. 72082790, 72085430, 72091590, 72091820, 72103090, 72104100, 72104900, 72106100, 72106900,

72107000, 72109010, 72109090, 72112350, 72112330, 72121010, 72123090, 72125090, 72126000, 72131090, 72254013. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of product under consideration.

15. It is noted that subject goods exported to India are identical to the goods produced by the domestic industry. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject countries in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

16. Rule 2(b) of the Antidumping Rules define domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term, 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers."

D.1. Submissions made by the domestic industry

17. The domestic industry submitted that the domestic producers constituting the domestic industry in the present sunset review are the same as in the original investigation. The domestic industry has ***% share in total Indian production of the subject goods during the POI. The share of domestic industry constitutes a major proportion in the total domestic production of subject goods in India in accordance with Rule 2(b) of the AD Rules.

D.2. Submissions made by other interested parties

18. No other interested party has made any submission regarding the standing of the domestic industry.

D.3. Examination by the Authority

19. The Authority notes that the sunset review application has been filed by the Indian Steel Association on behalf of JSW Steel Coated Products Limited and ArcelorMittal Nippon Steel India Limited. All the relevant information and documents have been provided by the Association as prescribed by the Authority.
20. The participating producers have not imported the subject goods from the subject countries and are claimed to be not related to any importer of the subject goods in India. JSW Steel Coated Products Limited is not related to any of the exporters of the subject goods from the subject countries. ArcelorMittal Nippon Steel India Limited is not related to any of the exporters of the subject goods from China PR. ArcelorMittal Nippon Steel India Limited has related companies in the European Union but there is nothing on the record to prove that the related companies have exported the subject goods to India during the POI.
21. As per the evidence available on record, the applicant companies namely, ArcelorMittal Nippon Steel India Limited and JSW Steel Coated Products Limited account for a major proportion in the domestic production of the like article in India. In view of the above, the Authority determines to hold that the applicant producers constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2(b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3), of the Rules supra.

E. CONFIDENTIALITY**E.1. Submissions made by the domestic industry**

22. The domestic industry has claimed confidentiality with respect to certain information which it considers confidential and business sensitive in nature. Sufficient non-confidential summary of confidential information has been provided at appropriate places to permit reasonable understanding of the substance of information contained therein.

E.2. Submissions made by other interested parties

23. No other interested party has made any submission with respect to the confidentiality claim.

E.3. Examination by the Authority

24. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties as per Rule 6(7).
25. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

26. The information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
27. A list of all the interested parties was uploaded on DGTR’s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN**F.1. Normal Value**

28. Under Section 9A (1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- i. *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

- ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
- comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*
- Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

F.2. Submissions made by the domestic industry

29. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the investigation:

- Chinese producers of the subject goods are operating under non-market economy conditions. Normal value for Chinese producers cannot be based on domestic selling prices and costs prevailing in China PR unless it is demonstrated that Chinese producers are operating under market economy conditions.
- In the original investigation as well, the Authority concluded that producers/exporters of subject product in China PR are operating under non-market economy conditions.
- European Commission ("EC") in its report has examined the market distortions that exist in specific sectors in China PR. The EC has found that there exist countrywide market distortions related to land, energy, capital, raw materials and other material inputs, and labour in China PR.
- The EC report also examined market distortions that exist in specific sectors including the steel, aluminum, chemical, and ceramics industries. Within these industries, the EC found that market distortions were caused by the Chinese government's intervention through all levels of government including the national, regional, and municipal levels via various planning and regulatory directives.
- ISA does not have access to accurate information regarding the cost of production and domestic selling price in the European Union for subject goods. Therefore, normal value for the China PR and European Union has been constructed by considering international price of raw material HR Coil. The price of other raw materials has been adopted based on domestic industry's experience. The raw material consumption has been taken on the basis of domestic industry's experience. Conversion costs have been considered based on the experience of the domestic industry. SGA costs and Finance costs have been considered based on the experience of the domestic industry. A profit margin of 5% has been considered for working out the normal value.
- Export price has been determined at ex-factory level. From the CIF export price, as per DGCIS import data. Relevant adjustments have been made to arrive at the ex-factory export price.
- The dumping margin so determined based on the comparison of normal value and export price at the ex-factory level is positive and significant both for China PR and European Union.
- It must be noted that the producers/exporters from China PR and European Union have not participated in the present sunset review investigation. Therefore, the Authority should proceed to determine dumping margin for exports from China PR and European Union based on the facts available.

F.3. Submissions made by other interested parties

30. None of the producer/exporter from subject countries have participated in the present sunset review investigation. The European Commission has submitted that the dumping calculation made by the domestic industry is flawed. The domestic industry has not presented any evidence that the European Union prices are dumped when exported to India or to any other third country; or that the European Union exports would be dumped in the future.

F.4. Examination by the Authority

31. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters of subject goods in subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority.
32. Since none of the producers/exporters of subject goods from subject countries have filed exporter's questionnaire response, the normal value and the export price for all producers/exporters from the subject countries have been determined based on the facts available.

China PR**F.4.1. Normal Value Determination**

33. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- a. In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
 - i. If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
 - ii. The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- b. In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China PR may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China PR.*
- c. The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with sub paragraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with sub paragraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- d. Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

34. It is noted that while the provision contained in Article 15(a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol requires criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since producers/exporters from China PR have not submitted response to supplementary questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para. 7 of Annexure I of the Rules.

35. As none of the producers from China PR have filed the questionnaire response, the normal value has been determined in accordance with Para 7 of Annexure I of the Rules. In the absence of sufficient information on record, regarding other methods enshrined in Para 7 of Annexure I of the Rules, the Authority has determined the normal value on "any other reasonable basis". The Authority has, therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of international price of raw material HR Coil, conversion costs and selling, general and administrative expenses based on experience of domestic industry and reasonable profit margin. The constructed normal value so determined for Chinese producers/exporters has been mentioned in the dumping margin table.

F.4.2. Determination of Export Price

36. As none of the producers/exporters from China PR have filed questionnaire response, export price from China PR has been determined considering volume and value of imports for the period of investigation as per DGCI&S published data. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission, bank charges and non-refundable VAT.

European Union

F.4.3. Determination of Normal Value

37. None of the producers/exporters from the European Union have participated in the present sunset review investigation and filed questionnaire response. In the absence of cooperation from the producers/exporters of product under consideration from the European Union, the Authority is not able to determine individual normal value for producers/exporters and is constrained to proceed with the principles of best available information in terms of Rule 6(8) of the Rules with regard to determination of normal value. The Authority has, therefore, constructed the normal value for the European Union on the basis of international price of raw material HR Coil, conversion costs and selling, general and administrative expenses based on experience of domestic industry and reasonable profit margin. The constructed normal value so determined for producers/exporters from EU is mentioned in the dumping margin table.

F.4.4. Determination of Export Price

38. None of the producers/exporters from the European Union have participated in the present sunset review investigation and filed questionnaire response. In the absence of cooperation from the producers/exporters of product under consideration from the European Union, the Authority has determined export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules considering volume and value of imports for the period of investigation as per DGCI&S published data. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission and bank charges. The normal value and export price so determined is mentioned in the dumping margin table.

F.5 Dumping Margin

39. Considering the normal value and the export price determined, as explained above, it is noted that the dumping margin for China PR, and the European Union is not only more than the de-minimis limit prescribed under the Rules but is also quite significant.

Country	Producer/Exporter	Normal Value (INR/MT)	NEP (INR/MT)	DM (INR/MT)	DM %	Range
China PR	Any Producer/Exporter	***	51,788	***	***	35-45%
European Union	Any Producer/Exporter	***	58,389	***	***	20-30%

G. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1. Submissions made by the domestic industry

40. The submissions made by the domestic industry with regard to injury and causal link are as under:

- a. In the original investigation, the Authority has already established a causal link between the dumped imports and injury to the domestic industry. Therefore, in the sunset review, the investigating authority must establish a link between the expiry of the duty and likelihood of recurrence of dumping and injury and there is no need to establish causal link between dumped imports and injury afresh during the review.
- b. Imports from the subject countries are significant both in absolute terms and in relation to total imports into India and Indian demand even after imposition of the anti-dumping duty.
- c. The subject countries have significant excess capacities and limited or static demand. They need export markets and India is one of the largest markets with significant and increasing demand. This can create influx of imports into the Indian market if duties are revoked. Moreover, plethora of tariffs and trade remedial measures are currently in effect against the subject countries in different markets. If the existing measures are not extended, India will be the only major export destination for subject countries without any trade remedial measures.
- d. The decline in imports during the last six months of the POI, i.e. from April 2020 to September 2020, is due to the Covid-19 pandemic. Imports will increase once the Covid-19 situation improves.
- e. Price undercutting from the European Union is negative and price undercutting from China PR is marginally positive.
- f. There is considerable price variation in export/import price from subject countries. Authority should also consider import transactions at lower prices that are undercutting domestic sales. Assessment of the Authority should not be limited to average price undercutting. Authority should assess the impact of low-priced import transactions on the sales of domestic industry. About 73% of the total imports from China PR and 35% of the total imports from the European Union are below the net sales realisation of the domestic industry.
- g. Anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods and which has been in force during the injury investigation period has been based on reference price mechanism. It was incumbent upon the producers/exporters from subject countries to keep the prices above reference price level.
- h. The Authority should also assess price undercutting by considering import price that was prevailing prior to the imposition of reference price based anti-dumping duty.
- i. In case of reference price based anti-dumping duty, actual import price cannot be simply relied upon for determining price undercutting because the element of anti-dumping duty is inbuilt in import/export price from the subject countries. Therefore, price undercutting should be assessed after deducting the 'inbuilt' anti-dumping duty in the import price. If the Authority excludes the average antidumping duty as calculated during the original investigation, the price undercutting would turn significantly positive.
- j. There is also a practice amongst the producers/exporters to specify delivery terms as CIF whereas the goods are delivered at ICD and as a result the price on record includes an additional price element of transportation cost from first port of import to ICD port. As per Customs Valuation Rules, the freight element from the first port of import to ICD is not to be included in the value for customs purposes and accordingly the same should also not be included while calculating landed value for an anti-dumping investigation.
- k. Producers/exporters from the subject countries were aware about the precise period of sunset review and therefore it was possible for them to keep the average prices higher for their exports to India. The Authority should investigate whether the increase in export price is based on economic rationale or is temporary.
- l. The Authority should not consider only the average import price because the import prices are not consistently higher during the POI. There is significant price variation in imports and the impact of import transactions at lower prices is required to be considered separately. Existence of price variation is relevant because many of the Indian customers quote the prices at which the imported goods are coming into the country and ask the domestic industry to match the imported prices.

- m. The current level of average import prices into India may not show the kind of price depression and suppression which the imports from subject countries are capable of exerting on the domestic industry once the protection granted in the form of reference price based anti-dumping duty is removed. If the anti-dumping duty is discontinued, the extent of price suppression and depression would change significantly.
- n. Production and capacity utilization of the domestic industry improved till 2019-20 and thereafter declined during the POI(A).
- o. Profitability of the domestic industry has improved after the imposition of anti-dumping duty. The improvement in profitability during the POI is also due to the temporary spike in steel prices globally. If the current anti-dumping duty protection is withdrawn, it will severely affect the profitability of the domestic industry going forward. The cash profits earned by the domestic industry have followed a similar trend as profitability.
- p. Quality of the goods produced by the domestic industry is at par with the imported goods. The domestic industry has sufficient capacity to cater to the Indian demand and therefore, availability of material is not a constraint. Delivery problems are also almost non-existent. Many of the Indian customers quote the prices at which the imported goods are coming into the country and ask the domestic industry to match the imported prices.
- q. Substantial imports of the subject goods are coming into India from Vietnam. Imports of the subject goods into India from Vietnam, may also be actually originating in China PR. It is also pertinent to mention that imports of subject goods from Vietnam started after imposition of anti-dumping duty on imports from China PR. The below table clearly depicts the increasing trend of imports from Vietnam:

	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Oct 19 to Mar 21)
Imports from Vietnam	1,14,856	468	11,291	74,257

- r. The landed value from Vietnam is lower than the landed value from China PR and also lower than the reference price of USD 822/MT as shown below:

Landed Value	Unit	POI (Oct 19 to March 21)
China PR	USD/MT	903.58
Vietnam	USD/MT	816.35

41. In the anti-circumvention investigation by the United States of America on *Corrosion-Resistant Steel Products (CORE)* from China PR, it was determined that the imports of certain corrosion-resistant steel products produced in Vietnam are circumventing the anti-dumping duty and countervailing duty orders on CORE from China PR.

G.2. Submissions made by other interested parties

42. The performance of domestic industry has improved during the injury investigation period and therefore the domestic industry is not suffering injury.
43. There are no imports from the European Union during the POI. The import price from European Union is higher than the average import price from other countries and therefore there is no injury due to imports from the European Union.

G.3. Examination by the Authority

44. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve an examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...".

45. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
46. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed in the present final finding.
47. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury.
48. The Authority has taken note of the various submissions made by the domestic industry on injury and causal link and has analysed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and the other interested parties.
49. In the present sunset review investigation, Authority has considered a longer period of 18 months from 1st October 2019 to 31st March 2021 as the POI so that it provides enough insight into the current and likely dumping and injury suffered by the domestic industry. Also, a longer POI was deemed appropriate in the present sunset review since trade in the first quarter of 2020-21 was impacted by Covid-19 and a longer period would be proper to assess the current injury and likelihood of injury to the domestic industry caused due to the alleged dumped imports.

a. **Assessment of demand**

50. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product under consideration in India, as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

S. No.	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI (A)	POI (Oct 19 to Mar 21)
1	Imports from Subject Countries	MT	2,58,098	71,610	78,531	70,137	1,05,206
		Trend	100	28	30	27	41
2	Imports from other Countries	MT	1,97,677	72,529	83,119	1,06,152	1,59,228
		Trend	100	37	42	54	81
3	Domestic sales of participating producers	MT	***	***	***	***	***
		Trend	100	119	133	141	212
4	Domestic sales of other producers	MT	***	***	***	***	***
		Trend	100	123	162	134	201
5	Total demand	MT	18,99,000	18,93,000	23,13,000	21,56,667	32,35,000
		Trend	100	100	122	114	170

51. It is seen that the demand for subject goods increased throughout the injury investigation period except for a slight decline during the POI (A).

b. **Volume effect of dumped imports**

i. **Import volume and share of subject countries**

52. The effects of the volume of dumped imports from the subject countries have been examined by the Authority as follows:

S. No.	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI (A)	POI (Oct 19 to Mar 21)
1	Subject Countries	MT	2,58,098	71,610	78,531	70,137	1,05,206
A	China PR	MT	2,54,954	71,088	76,712	69,353	1,04,029
B	European Union	MT	3,145	522	1,819	785	1,177
2	Subject countries import in relation to						
A	Domestic Industry Production	%	***	***	***	***	***
B	Consumption	%	14%	4%	3%	3%	3%
C	Total imports	%	57%	50%	49%	39%	39%

53. The Authority notes that imports from subject countries have declined during the POI (A) in absolute terms as well as in relation to total Indian production, total Indian consumption and total imports.

c. **Price effect of dumped imports**

54. With regard to the effect of dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.

55. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of sales and Net Sales Realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports from the subject countries.

i. **Price undercutting**

56. Price undercutting has been determined by comparing the landed price of imports from the subject countries with the net sales realisation of the domestic industry in India.

S. No.	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Oct 19 to Mar 21)
1	Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***	***
2	Landed Price					

A	China PR	Rs/MT	57,110	69,400	62,956	66,115
B	European Union	Rs/MT	68,920	1,05,862	85,397	77,918
C	Subject countries	Rs/MT	57,254	69,666	63,475	66,247
3	Price Undercutting					
A	China PR	Rs/MT	***	(***)	***	***
B	European Union	Rs/MT	(***)	(***)	(***)	(***)
C	Subject countries	Rs/MT	***	(***)	(***)	***
4	Price Undercutting					
A	China PR	%	***	(***)	***	***
B	European Union	%	(***)	(***)	(***)	(***)
C	Subject countries	%	***	(***)	(***)	***
5	Price Undercutting					
A	China PR	Range	5-15%	Negative	0-10%	0-10%
B	European Union	Range	Negative	Negative	Negative	Negative
C	Subject countries	Range	5-15%	Negative	Negative	0-10%

57. The Authority notes that the price undercutting is negative for the imports from European Union. The price undercutting is marginally positive for the imports from China PR.

ii. Price suppression/depression

58. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period.

S. No.	Particulars	UQM	2017-18	2018-19	2019-20	POI (Oct'19 to Mar'21)
1	Landed price – Subject countries	Rs/MT	57,254	69,666	63,475	66,247
		Indexed	100	122	111	116
2	Cost of sales per Unit – Domestic	Rs/MT	***	***	***	***
		Indexed	100	110	99	104
3	Selling price per Unit – Domestic	Rs/MT	***	***	***	***
		Indexed	100	110	101	108

59. The Authority notes that the prices of the domestic industry increased till 2018-19 when the import prices were also increasing. Thereafter, when the import prices declined during 2019-20 and POI as compared to 2018-19, the prices of the domestic industry also declined during the same period.

d. **Impact on economic parameters of the domestic industry**

60. Annexure - II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry shall include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity, factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

i. **Capacity, production, capacity utilization and sales**

61. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period.

S. No.	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI (A)	POI (Oct 19 to Mar 21)
1	Capacity	MT	***	***	***	***	***
		Indexed	100	100	101	109	163
2	Self-production	MT	***	***	***	***	***
		Indexed	100	110	113	111	166
3	Job work production	MT	-	-	***	***	***
		Indexed	-	-	100	154	232
4	Total Production	MT	***	***	***	***	***
		Indexed	100	110	124	128	191
5	Capacity Utilisation	%	***	***	***	***	***
		Indexed	100	110	112	102	102
6	Domestic sales	MT	***	***	***	***	***
		Indexed	100	119	133	141	212

62. It is seen that:

- The domestic industry has expanded its capacity during the POI.
- The capacity utilization of domestic industry has increased till 2019-20 but declined in the POI (A).
- The total production and domestic sales increased during the injury period.

ii. **Market share of domestic industry in demand**

63. The effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry has been examined as below:

S. No.	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI (A)	POI (Oct'19 to Mar'21)
1	Subject countries	%	14%	4%	3%	3%	3%
		%- Range	10-20	0-10	0-10	0-10	0-10
2	Other countries	%	10%	4%	4%	5%	5%
		%- Range	5-15	0-10	0-10	0-10	0-10
3	Domestic industry	%	***	***	***	***	***
		%- Range	30-40	35-45	35-45	35-45	35-45

64. It is seen that the market share of the domestic industry increased in 2018-19 then declined in 2019-20 and thereafter again increased in the POI (A).

iii. Inventory

65. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given below: -

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (A)
Average inventory	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	112	168	110

66. It is seen that the average inventory of the domestic industry increased till 2019-20 and thereafter declined during the POI(A).

iv. Profit or loss, cash profits and return on investment

67. Performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

S. No.	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI (A)	POI (Oct 19 to Mar 21)
1	Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***	***
		Indexed	100	110	99	104	104
2	Selling price	Rs/MT	***	***	***	***	***
		Indexed	100	110	101	108	108
3	Profit / Loss	Rs Lacs	***	***	***	***	***
		Indexed	100	124	150	189	284
4	Profit / Loss	Rs/MT	***	***	***	***	***
		Indexed	100	104	113	134	134
5	Cash profits	Rs Lacs	***	***	***	***	***
		Indexed	100	124	151	187	281
6	Cash profits	Rs/MT	***	***	***	***	***
		Indexed	100	104	113	133	133
7	PBIT	Rs Lacs	***	***	***	***	***
		Indexed	100	124	150	185	278
8	PBIT	Rs/MT	***	***	***	***	***
		Indexed	100	104	112	131	131
9	Return on capital employed	%	***	***	***	***	***
		Indexed	100	94	80	106	106

68. It is seen that the profitability of the domestic industry has improved after the imposition of anti-dumping duty.

v. Employment, wages and productivity

69. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity has been examined.

S. No.	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI (A)	POI (Oct 19 to Mar 21)
1	No of employees	Nos	***	***	***	***	***
		Indexed	100	101	100	104	104
2	Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***	***
		Indexed	100	110	113	111	111
3	Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***	***
		Indexed	100	110	113	106	106

70. It is seen that productivity per day and productivity per employee has increased during the injury investigation period.

vi. Growth

71. Examination of growth in economic parameters of the domestic industry during the injury period is shown below.

SN	Particulars	2018-19	2019-20	POI (A)
1	Production	***	***	***
2	Domestic Sales	***	***	***
3	Profit/(Loss) per MT	***	***	***
4	Profit/(Loss) - (Rs Lacs)	***	***	***
5	Cash Profit - (Rs Lacs)	***	***	***
6	PBIT - (Rs Lacs)	***	***	***
7	ROI %	***	***	***

72. It is seen that volume and price parameters of the domestic industry show a positive growth.

vii. Magnitude of dumping

73. It can be seen that the dumping margin for subject countries is not only more than de-minimis but also significant.

viii. Ability to raise fresh capital

74. The domestic industry comprises of companies, which are multi-product companies. These companies have been doing fairly well over the injury period. Therefore, their ability to raise fresh capital remains intact.

H. FACTORS RELEVANT TO CAUSAL LINK

75. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority has examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

i. Volume and price of imports from third countries

76. Imports from third countries have increased in absolute terms and in relation to total imports.

Sr. No.	Particulars	UQM	2017-18	2018-19	2019-20	POI (A)	POI (Oct 19 to Mar 21)
1	Imports from Subject Countries	MT	2,58,098	71,610	78,531	70,137	105,206
		Trend	100	28	30	27	41
2	Imports from Other Countries	MT	1,97,677	72,529	83,119	1,06,152	1,59,228
		Trend	100	37	42	54	81

77. It is noted that majority of the imports from non-subject countries are imports from Korea RP and Vietnam. Imports from Korea RP are at prices significantly higher than import prices from subject countries. Imports of subject goods into India from Vietnam are at lower prices.

ii. **Contraction in Demand and / or change in pattern of Consumption**

78. It is seen that the demand for subject goods increased throughout the injury investigation period except during the POI (A).

iii. **Development of technology**

79. The Authority notes that technology for production of the product has not undergone any change. Development in technology is, therefore, not a possible factor of injury.

iv. **Trade restrictive practices**

80. The Authority notes that there are no trade restrictive practices, which could have caused injury to the domestic industry.

v. **Export performance**

81. It is seen that the exports of the domestic industry have remained more or less in the same range during the injury investigation period. In any case, Authority has considered data for the domestic operations only in its injury analysis.

vi. **Performance of other products**

82. The Authority has considered the data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, performance of other products produced and sold by the domestic industry cannot be a possible cause of injury to the domestic industry.

1. **MAGNITUDE OF INJURY MARGIN**

83. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been compared with the landed price from the subject countries for calculating injury margin.

84. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

85. Based on the landed price and NIP determined as above, the proposed injury margin for producers/exporters from subject countries as determined by the Authority is provided in the table below.

Country	Producer/Exporter	NIP (INR/MT)	Landed Price (INR/MT)	IM (INR/MT)	IM %	Range
China PR	Any Producer/Exporter	***	66,115	(***)	(***)	(5-15)
European Union	Any Producer/Exporter	***	77,918	(***)	(***)	(20-30)

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING & INJURY**J.1. Submissions made by the domestic industry**

86. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the sunset review investigation:

- a. The performance of the domestic industry has shown improvement as a positive outcome of the anti-dumping duty levied by the Authority. However, once the anti-dumping duty is removed the subject goods from China PR would enter the Indian market unabated due to excess capacities in China PR and limited or static demand in their local market.
- b. As per *MySteel Network Report* with a capacity utilization of 64.54% in 2020, the Chinese producers have idle capacities of 11.03 million tons, which could be utilised to produce PUC for export destinations including India.

S. No.	Particulars	Source	Million Tons
A	China's Domestic Demand	MySteel Report	13.50
B	Total Export from China	MySteel Report	6.57
C	Total Production	A+B	20.07
D	Capacity Utilisation	MySteel Report	64.54%
E	Production Capacity	C/D	31.10
F	Idle Capacity	E-C	11.03

- c. India is a large market with significant and increasing demand. Demand is approximately 2.1 million tons in POI(A).

Demand (MT)	2017-18	2018-19	2019-20	POI (A)	POI (Oct 19 to Mar 21)
	18,99,000	18,93,000	23,13,000	21,56,667	32,35,000

- d. The idle capacity in China PR is more than 5 times the total annual demand of subject goods in India.
- e. Chinese producers hold production capacities of 31.10 million tons and their domestic demand is at 13.50 million tons. Therefore, chinese producers have 17.60 million tons of capacity available for exports (which is 57% of the total capacity), which can be utilised for export markets.

Particulars	Source	Million Tons
Production Capacity	As per S. No. E in above table	31.10
China's Domestic Demand	MySteel Report	13.50
Capacity Available for Export		17.60
Capacity Available for Export in relation to total capacity		57%

- f. The average export price from China PR to India of colour coated steel product has remained higher than the export price to other countries:

PUC	Unit	2018	2019	2020
FOB Export Price to rest of the World	USD/MT	826	737	717

Source: ISSB database

PUC	Unit	2018-19	2019-20	POI
Import prices into India	USD/MT	861	772	801

Source: DGCI&S data

- g. Indian market is more lucrative in terms of prices for exporters from China PR as compared to other countries.
- h. Majority of exports from China PR to third countries are at dumped and injurious prices.

Particulars	Unit	Dumping Margin	Injury Margin	Price Undercutting
Total Exports from China PR during POI	MT	***	***	***
Exports having positive Dumping margin/injury margin/price undercutting	MT	***	***	***
Exports having positive dumping margin/injury margin/price undercutting	%	95%	38%	78%

Source: ISSB Data

- i. Substantial share of exports from China PR to third countries have positive dumping margin. Majority of exports from China PR to third countries are also significantly below the domestic selling price and the non-injurious price of domestic industry. If these exports to third countries are diverted to India, upon withdrawal of anti-dumping duty, there is clear likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury from China PR.
- j. Current imports of the PUC from the European Union are insignificant. However, the low imports from the European Union are also due to anti-dumping duty in force. The imports from the European Union are likely to increase if anti-dumping duty is revoked. Moreover, demand of the subject goods in the European Union is stagnant.

Million Tonnes	2017	2018	2019	2020
Demand*	5.32	5.25	5.54	5.25

*Source: EUROFER and ISSB based on production, import and export of EU

- k. The European Union has capacity in excess of demand of at least 4,70,000 MT in 2020 and the capacity in excess of production is 6,90,000 MT in 2020. Surplus capacity in the European Union in excess of total EU demand is nearly 22% of Indian demand and surplus capacity in the European Union in excess of total EU production is nearly 32% of Indian demand.

Million Tonnes	Source	2018	2019	2020
Production (C)	EUROFER	4.93	5.14	5.03
Import	ISSB	0.94	1.00	0.83
Export	ISSB	0.62	0.61	0.61
Demand (A)		5.25	5.54	5.25
Capacity (B)		5.60	5.84	5.72
Capacity in excess of demand (B) – (A)		0.35	0.30	0.47
Capacity in excess of production (B) –(C)		0.67	0.70	0.69

- l. Whenever the domestic demand in the European Union has declined, the producers have focused on the export markets. The table below clearly shows the correlation between increase in exports and decline in domestic demand:

Year	Demand – (Source: Derived from ISSB and EUROFER)	Export from EU (Source: ISSB)
2011	5.12	0.51
2012	4.58	0.64
2013	4.44	0.75
2014	4.63	0.70

- m. As per the analysis done by the applicant with the help of ISSB data, 19% of the exports by the European Union to the third countries are at dumped prices.
- n. Almost all major countries with significant market size have already imposed or continued trade remedial measures on import of subject goods from subject countries. If anti-dumping duty is discontinued, it will lead to recurrence of injury to the Indian domestic producers because of significant influx of dumped imports from subject countries.
- o. Following countries have imposed/continued trade remedy measures on imports of subject goods:

S. No.	Importing Country	Description of product	Type of measure	Country/ies investigated
1.	Australia	Painted steel strapping	Anti-dumping	China PR
2.	Chinese Taipei	Flat rolled steel products, plated or coated with zinc or zinc-alloys	Anti-Dumping	China PR, Korea
3.	Mexico	Certain coated flat steel products	Anti-Dumping	China PR and Taiwan
4.	USA	Corrosion-Resistant Steel Products	Anti-Dumping	China PR, Italy, Korea, Taiwan and India
5.	USA	A Corrosion-Resistant Steel Products	Countervailing duty	China PR, Italy, Korea, Taiwan and India
6.	Malaysia	Pre-painted, painted or colour-coated steel coils	Anti-Dumping	China PR and Vietnam
7.	Canada	Corrosion-resistant steel sheet	Anti-dumping	China PR
8.	European Union	Organic coated steel products	Anti-dumping	China PR
9.	European Union	Organic Coated steel products	Countervailing	China PR
10.	European Union	Corrosion resistant steel	Anti-dumping	China PR
11.	Indonesia	Coated steel	Anti-dumping	China PR

S. No.	Importing Country	Description of product	Type of measure	Country/ies investigated
12.	Pakistan	Colour coated steel coils/sheets	Anti-dumping	China PR
13.	Chinese Taipei	Flat-rolled steel products, plated or coated with zinc or zinc-alloys	Countervailing	China PR
14.	Thailand	Painted hot dip plated or coated with aluminium-zinc alloys of cold-rolled steel	Anti-dumping	China PR
15.	Turkey	Painted Galvanized Sheet Metal (Cold Rolled)	Anti-dumping	China PR
16.	Ukraine	Rolled products with corrosion resistant coating	Anti-dumping	China PR
17.	Vietnam	Flat rolled iron or non-alloy steel, painted, plated or coated	Anti-dumping	China PR
18.	GCC	Flat rolled Steel	Safeguard	European Union
19.	South Africa	Certain Flat Rolled Steel Products	Safeguard	Sweden, Belgium, Germany

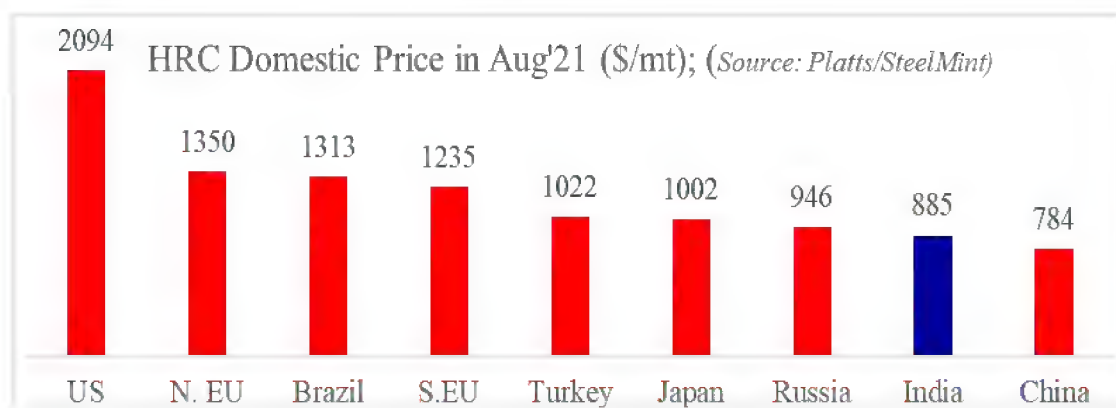
- p. If the existing measures are not extended, India will be the only major export destination for subject countries without any trade remedial measures.
- q. The Ministry of Finance vide Notification No.2/2021-Customs dated 1st February 2021 has reduced the basic customs duty (MFN rate) on imports of the subject goods into India from 12.5% to 7.5%. This reduction in the basic customs duty will create incentive for the imports of subject goods from China PR and European Union.
- r. The anti-dumping duty on the subject goods was imposed w.e.f. 11th January 2017. After imposition of anti-dumping duty on subject goods, the imports of aluminium and zinc coated flat products into India increased significantly from 2017-18 onwards.

Aluminium and Zinc coated flat products	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	October'17 to September'18
Total Imports from China, Vietnam and Korea	MT	18,220	34,721	1,45,805	2,09,676

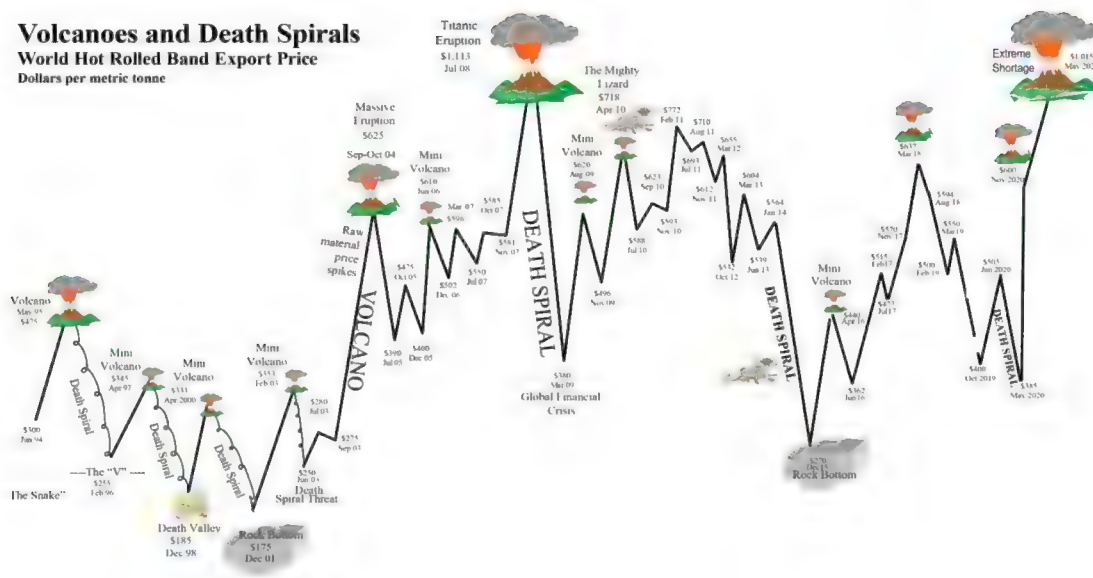
Source: Final Findings – 21st February 2020 - Anti-dumping Investigation concerning imports of Aluminium and Zinc coated flat products

- s. Imports of Aluminium and Zinc coated flat products increased to 1,45,805 MT in 2017-18 and to 2,09,676 MT in October 2017 to September 2018 period. Aluminium and Zinc coated flat product is a penultimate stage product and is used for making the PUC. With the imposition of anti-dumping duty on PUC, importers/users started importing aluminium and zinc coated flat products at dumped prices and undertaking painting/colour coating process in India. Anti-dumping duty investigation was initiated on imports of aluminium and zinc coated flat products and anti-dumping duty was recommended on their imports by the Authority vide the final findings dated 21st February 2020, which was implemented on 23rd June 2020. It is submitted that if the anti-dumping duty is not continued on the final product, the existing anti-dumping duty on import of aluminium and zinc coated flat steel products will become redundant as importers/users will again shift to the imports of subject goods in increased quantities.

- t. The Authority has recommended continuation of anti-dumping duty on hot rolled flat steel products and cold rolled flat steel products vide final findings dated 14th September 2021. Substantial part of the domestically manufactured hot rolled and cold rolled flat steel products is used for production of subject goods. If the anti-dumping duty is not continued on the import of the subject goods, it would weaken the remedial effect of anti-dumping duty on import of hot rolled and cold rolled flat steel products.
- u. The product under consideration is the last product in the value chain of flat rolled steel products. If anti-dumping duty is not continued on imports of this final stage finished product in flat rolled steel category, full remedial effect of anti-dumping duty on other flat rolled steel products would not be achieved.
- v. The Government of India is encouraging domestic production of speciality steel like the colour coated steel products through production linked incentive (PLI) scheme. Substantial investments for product under consideration by Indian domestic producers are already in pipeline.
- w. The subject goods are also important as they offer corrosion resistant properties. India loses 5-7% GDP every year due to corrosion.
- x. The domestic steel prices in India have remained lower than international steel prices despite global boom as shown in the table below:



- y. The steel prices are cyclical in nature. In 2008 hot rolled/cold rolled steel prices were higher and similar to the current level. In 2009, there was sudden decline in prices and the prices reduced by approximately 65%. Steel prices crashed and reached their lowest levels in December 2015. Prices crashed by almost 52% during this period as compared to 2014 and this is when the domestic producers in India requested Government of India for imposition of anti-dumping duty on various steel products. The below chart clearly depicts the volcanoes and death spirals of the steel market:



Source: World Steel Dynamics – Key Developments 2020

- z. The steel prices are currently on the higher side globally due to high raw material prices and supply side shortage. However, they are not representative of future trends. In fact, going by the cyclical trend of steel prices, it is expected that prices would decline in coming quarters. The word steel dynamics report has projected sharp decline in steel prices in coming quarters i.e. by September 2022. It has projected decline of nearly 48% in the global steel prices by September 2022.
- aa. Historic trend of prices shows that the decline in prices happen suddenly within 3 to 4 quarters and there is no time to react and seek trade remedial measures at that point of time. In 2015, when the steel prices crashed, a number of steel companies went into bankruptcy and liquidation proceedings as they were not able to sustain the onslaught of low prices. Some examples of companies which went into liquidation are:
- Bhushan Power & Steel Ltd.
 - Essar Steel India Ltd.
 - Monnet Ispat and Energy Ltd.
 - Bhushan Steel Ltd.
 - Electrosteel Steels Ltd.
 - Usha Martin Ltd.
 - Asian Colour Coated Ispat Ltd.
- bb. A healthy and competitive steel industry is critical for nation building. The steel industry in India constitutes around 2% of GDP and generates substantial direct (approx. 5 lakhs) and indirect employment (approx. 20 lakhs).
- cc. The domestic industry supports a variety of linked downstream services such as transport services, port facilities, power supply and other supply-chain related activities. Adverse impact on steel industry will be felt on these downstream industries as well.
- dd. There are many producers of subject goods in India and there is healthy competition in the Indian market. Continuation of anti-dumping duty would not lead to monopolistic or oligopolistic situation in the Indian market for the subject goods:
- ArcelorMittal Nippon Steel India Limited (Formerly Essar Steel India Limited)
 - JSW Steel Coated Products Limited
 - Tata Bluescope Steel Private Limited
 - Tata BSL

- Bhushan Power and Steel Limited
- National Steel and Agro Industries Limited
- Asian Colour Coated Ispat Limited
- Uttam Galva Steels Limited
- Indian Steel Corporation
- La Tim Metal & Industries Ltd
- Manaksia Steels Limited
- Jindal (India) Limited
- Colorshine Coated Pvt. Ltd.
- Prabhat Global Colour Coated Pvt. Ltd.
- Colour Roof (India) Ltd.
- Ralco Steels Pvt. Ltd.

ee. Anti-dumping duty in the present reference price form had no adverse impact on public interest as no duty was collected during the injury investigation period. We understand that no duty was paid by importers or users upon import of subject goods into India from the subject countries as imports were made above the reference price. However, assuming the existence of fixed/ad-valorem duty, the domestic industry is also providing following examples to demonstrate insignificant impact of duty on the user industry and final consumers in white goods.

Example 1: Refrigerator

Refrigerator price	Rs. 20,000
Estimated Price of Colour Coated per MT	Rs. 100,000
Assumed Anti-dumping duty (ADD) @ 20%	Rs. 20,000
Colour Coated Steel used in Refrigerator	***
ADD-impact per Refrigerator	0-2%

Example 2: Washing Machine

Washing Machine price	Rs. 15,000
Estimated Price of Colour Coated per MT	Rs. 100,000
Assumed Anti-dumping duty (ADD) @ 20%	Rs. 20,000
Colour Coated Steel used in Washing Machine	***
ADD-impact per Washing Machine	0-2%

Example 3: Air Conditioner

Air Conditioner price	Rs. 30,000
Estimated Price of Colour Coated per MT	Rs. 100,000
Assumed Anti-dumping duty (ADD) @ 20%	Rs. 20,000
Colour Coated Steel used in Air Conditioner	***
ADD-impact per Air Conditioner	0-2%

Example 4: Microwave Oven

Microwave Oven price	Rs. 9000
Estimated Price of Colour Coated per MT	Rs. 100,000
Assumed Anti-dumping duty (ADD) @ 20%	Rs. 20,000
Colour Coated Steel used in Microwave Oven	***
ADD-impact per Microwave Oven	0-2%

- ff. As is evident from the above tables, the impact of 20% anti-dumping duty is 1% or less than 1% on the final product in case of white goods.

J.2. Submissions made by the other interested parties

87. The following submissions have been made by the other interested parties during the course of the sunset review investigation:

- a. The imports from the subject countries have decreased significantly since measures were imposed and EU exports represent less than 1% market share during the injury period.
- b. EU prices are 13% higher than Chinese prices and 59% higher than the average price of imports to India.
- c. The measures have been effective as the imports have decreased significantly and the situation of the domestic industry has improved. The domestic industry is in a rather good position. Domestic sales have increased by 41% of the participating domestic producers and by 34% by all other producers of colour-coated steel in India, on account of significant decrease of imports from the subject countries. Demand has increased by 14 indexed points. Market share of the domestic producers has increased from 30-35% to 45-55%. Capacity, production and capacity utilization has increased. Profitability has increased by 31 indexed points; Cash profits have increased by 31 indexed points and Productivity has increased steadily. The domestic industry has been able to raise its selling price by 11 indexed points.
- d. Given this situation of the domestic industry, it is very difficult to argue that injury is likely to recur. If the domestic industry would experience any difficulties in the future, this would not be caused by the EU exports, as they are unlikely to be dumped and volumes are unlikely to increase significantly.
- e. The Applicant has wrongly based their conclusion on the *Mysteel Network Report* that is focusing on Chinese steel market only and therefore inadequately judged the development of the EU exports.
- f. The Applicants unjustly claim that the subject countries have significant excess capacities and limited demand and therefore the anti-dumping duties should be extended not to create an influx of imports to India. However, no evidence of excess capacity in the EU has been provided.
- g. As regards the COVID-19 pandemic it is recalled that it has affected producers of the product concerned all around the world and the situation is not specific to the Indian market. The World Steel Association also confirmed that the impact of the coronavirus pandemic on the sector turned out to be less than previously foreseen.
- h. As per World Steel Association, steel demand will grow by 5.8% in 2021 and will see further growth of 2.7% in 2022. Considering that in the EU, recovery in 2021 and 2022 is expected to be healthy, driven by a recovery in all steel-using sectors, especially automotive and public construction initiatives, there is no freely available capacity in the EU that would generate exports to India after gradual return to normality.
- i. The dumping calculation is flawed as the applicants have not presented any evidence that the EU prices are dumped when exported to India or to another third country, or that the EU exports would be dumped in the future.

J.3. Examination by the Authority

88. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from China PR and the European Union. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

89. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia, factors which are relevant for threat of injury and the same factors may be used for likelihood analysis in a sunset review as well:

- a) A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
- b) Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- c) Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
- d) Inventories of the article being investigated.

90. The Authority has examined the factors listed in clause (vii) of Annexure II of the Rules to the extent deemed appropriate and also other relevant factors, which could have a bearing on the likelihood of recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

91. In *Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. vs Designated Authority*, the Hon'ble CESTAT observed as follows with regard to examination of likelihood of injury in a situation where the condition of domestic industry has improved:

"With respect to the injury determination, if the anti-dumping duty has had the desired effect, the condition of the Domestic Industry would be expected to have improved during the period the anti-dumping duty was in effect. Therefore, the assessment whether injury will continue, or recur, would entail a counter-factual analysis of future events, based on projected levels of dumped imports, prices, and impact on domestic producers. Thus the D.A. has to address the question as to whether the Domestic Industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted."

92. In *Borax Moraji Limited vs Designated Authority*, the Hon'ble Tribunal noted that:

"The expression 'likely to lead to recurrence' would take within its fold situation where the dumping and injury may not exist at the time of review due to the imposition and continuance of anti-dumping duty which, if allowed to cease to have effect on the expiry of five years, is likely to lead to recurrence of dumping and injury."

93. The WTO Appellate Body noted in *US- Corrosion-Resistant Steel Sunset Review (Japan)* [DS 244] that the determination in a sunset review investigation is a prospective examination, where the authorities must undertake a forward-looking analysis and seek to resolve the issue of what would be likely to occur if the duty was terminated. The Appellate Body noted:

"105. This appeal concerns the obligations that apply to investigating authorities with respect to the second of these conditions. It focuses on the particular disciplines with which authorities must comply in determining, in accordance with Article 11.3, "that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping". In this Report, we refer to this determination as the "likelihood determination". The likelihood determination is a prospective determination. In other words, the authorities must undertake a forward-looking analysis and seek to resolve the issue of what would be likely to occur if the duty were terminated."

94. Thus, it is noted that in absence of current injury to the domestic industry, the Authority is required to examine likelihood of recurrence of injury in the event of revocation of duty.

95. In absence of participation of producers/exporters from subject countries, the Authority has relied on facts available for conducting the likelihood analysis.

A.1**a. Continued Imports in substantial quantities**

96. The volume of imports during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI (A)	POI
Total Imports	MT	4,55,776	1,44,139	1,61,650	1,76,289	2,64,434
A) Subject Countries	MT	2,58,098	71,610	78,531	70,137	1,05,206
China PR	MT	2,54,954	71,088	76,712	69,353	1,04,029
European Union	MT	3,145	522	1,819	785	1,177
B) Other countries	MT	1,97,677	72,529	83,119	1,06,152	1,59,228

97. It is seen that imports from subject countries continue to be significant both in absolute terms and in relation to total imports into India and Indian demand even after imposition of anti-dumping duty.

b. Continuation of dumping from subject countries

98. It is noted that the subject countries continue to dump the subject goods into India despite existence of anti-dumping duty in force.

c. Surplus Capacity in China PR

99. It is noted that no producer/exporter from China PR has participated in the subject sunset review. Therefore, no information is available with the Authority based on questionnaire response of producers/exporters from China PR.

100. The Authority has relied on the latest available information from MySteel Network report regarding total production capacity of the subject goods in China PR:

S. No.	Particulars	Source	Million Tons
A	China PR's Domestic Demand	MySteel Report	13.50
B	Total Exports from China PR	MySteel Report	6.57
C	Total Production	A+B	20.07
D	Capacity Utilisation	MySteel Report	64.54%
E	Production Capacity	C/D	31.10
F	Idle Capacity	E-C	11.03

101. The Authority has relied on the JPC report for the demand of subject goods in the Indian market. Details are provided below:

Demand (MT)	2017-18	2018-19	2019-20	POI (A)	POI (Oct 19 to Mar 21)
	18,99,000	18,93,000	23,13,000	21,56,667	32,35,000

102. It is noted that the surplus capacity available in China PR is more than five times the total annual demand of subject goods in India. In addition, there were no elements found that could indicate that the domestic demand in China PR or in other third country markets could absorb the available surplus capacity.

d. Surplus capacity in the European Union

103. The Authority notes that no producer/exporter from the European Union has participated in the subject sunset review. Therefore, no information is available with the Authority based on questionnaire response of the producers/exporters from the European Union. The European Commission has also not provided any details regarding the production capacity, demand and excess capacity for subject goods in the European Union.

104. The demand for the subject goods in the European Union is as under:

Million Tonnes	2017	2018	2019	2020
Demand*	5.32	5.25	5.54	5.25

Source: EUROFER and ISSB * Derived based on production, import and export of EU

105. It is observed that the demand in the European Union is stagnant.

106. The production data and capacity of the subject goods in the European Union is shown below:

	Production (Million Tonnes)	
Year	As per EUROFER	As per EU Regulation - Anti-dumping duty expiry review on imports of certain organic coated steel products originating in the People's Republic of China following an expiry review
2014	4.57	4.40
2015	4.58	4.40
2016	4.87	4.76
2017	4.94	4.75
2018	4.93	N/A
2019	5.14	N/A
2020	5.03	N/A

107. It is observed that the production data of the European Union from EUROFER for 2014 to 2018 is comparable with the production data in the final findings dated 2nd May 2019 concerning imports of certain organic coated steel products originating in China PR. Since data for the latest period is not available in the European Commission findings dated 2nd May 2019, the data obtained from EUROFER for 2018 to 2020 has been considered by the Authority to ascertain the production and capacity of the European Union.

108. The Authority notes that as per the European Commission findings dated 2nd May 2019, the capacity utilization of EU steel industry has been consistent as noted in the table below:

Particulars	2014	2015	2016	2017	Average
Production (MT)	44,02,079	44,04,178	47,69,698	47,52,003	45,81,990
Capacity (MT)	50,76,892	51,13,417	53,61,693	53,39,200	52,22,801
Utilization (%)	87%	86%	89%	89%	88%

109. Thus, based on the production of the year 2020 and average capacity utilization of 88%, the capacity of the European Union has been derived. The excess capacity at disposal of the European Union is given below:

Million Tonnes	Source	2018	2019	2020
Production (C)	EUROFER	4.93	5.14	5.03
Import	ISSB	0.94	1.00	0.83
Export	ISSB	0.62	0.61	0.61
Demand (A)	Derived	5.25	5.54	5.25
Capacity (B)	Derived	5.60	5.84	5.72
Capacity in excess of demand (B) – (A)	Derived	0.35	0.30	0.47
Capacity in excess of production (B) –(C)	Derived	0.67	0.70	0.69

110. The Authority notes that the European Union has capacity in excess of demand of at least 4,70,000 MT in 2020. The capacity in excess of production is 6,90,000 MT in 2020. Surplus capacity in the European Union in excess of total demand is nearly 22% of Indian demand and surplus capacity in European Union in excess of total production is nearly 32% of Indian demand.

The independent reports on record thus indicate that there are huge surplus capacities available with the subject countries.

e. **Trade Remedial Measures by other countries**

111. As per the information on record, there are currently a number of trade remedial measures imposed against the imports of subject goods from subject countries by other countries.
112. The Authority relies on the MySteel Network Report which states that there are about 20 trade remedial investigations going on concerning imports of colour coated plates and coils from China PR.
113. The Authority notes that almost all the countries having substantial production base for the product under consideration have put in place trade remedy measures against imports of subject goods from subject countries.

f. **Price attractiveness**

114. The information with respect to price attractiveness of the Indian market for Chinese producers/exporters is given in the tables below:

PUC	Unit	2018	2019	2020
FOB Export Price (World)	USD/MT	826	737	717

Source: ISSB Data

PUC	Unit	2018-19	2019-20	POI
Import prices into India	USD/MT	861	772	801

Source: DGCI&S data

115. It can be seen that exports of subject goods to third countries by the producers/exporters from China PR are at prices below the export price to India. Thus, the Indian market is price attractive for the exporters/producers from China PR.

g. **Exports to third countries at dumped and injurious prices**

116. The Authority notes that the information available regarding exports of subject goods from China PR during POI shows that majority of exports from China PR to third countries are at dumped and injurious prices.

Particulars	Unit	Dumping Margin	Injury Margin	Price Undercutting
Total Exports of subject goods from China PR during POI	MT	***	***	***
Exports having positive dumping margin/injury margin/price undercutting	MT	***	***	***
Exports having positive dumping margin/injury margin/price undercutting	%	95%	38%	78%

Source: ISSB Data

117. It is observed that almost all exports of the PUC from China PR to third countries are at dumped prices. Further, 38% exports of the PUC from China PR to third countries are at prices below the NIP determined for the domestic industry and 78% exports of the PUC from China PR to third countries are at prices below the selling price of the domestic industry.

118. The Authority notes that 29% of the exports of the PUC by the European Union to the third countries are at dumped prices.

Third countries exports from EU during POI

Particulars	Unit	Dumping Margin
Total Exports from European Union	MT	***
Volume having positive dumping margin	MT	***
Volume having positive dumping margin	%	29%

Source: ISSB

h. **Change in pattern of trade subsequent to imposition of anti-dumping duty on subject goods.****A.2**

119. The Authority notes that the anti-dumping duty on the subject goods was imposed w.e.f. 11th January 2017. After imposition of anti-dumping duty on subject goods, the imports of aluminium and zinc coated flat products into India increased significantly from 2017-18 onwards.

Aluminium and Zinc coated flat products	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	October'17 to September'18
Total Imports from China, Vietnam and Korea	MT	18,220	34,721	1,45,805	2,09,676

Source: Final Findings – 21st February 2020 - Anti-dumping Investigation concerning imports of Aluminium and Zinc coated flat products

120. It is observed that after imposition of the anti-dumping duty on the subject goods, imports of aluminium and zinc coated flat products increased to 1,45,805 MT in 2017-18 and 2,09,676 MT in October 2017 to September 2018. Aluminium and Zinc coated flat products is a penultimate stage product and is used for making the PUC. With the imposition of an anti-dumping duty on the PUC, importers/users started importing aluminium and zinc coated flat products at dumped prices and undertaking painting/colour coating process in India. The investment required for setting up colouring/painting line is insignificant.

121. Anti-dumping duty investigation was initiated on imports of aluminium and zinc coated flat products and anti-dumping duty was recommended on their imports by the Authority vide the final findings dated 21st February 2020, which was implemented on 23rd June 2020.

i. **Protection granted on hot rolled and cold rolled steel products**

122. The Authority has recommended continuation of anti-dumping duty on hot rolled flat steel products and cold rolled flat steel products vide final findings dated 14th September 2021. Substantial part of the domestically manufactured hot rolled and cold rolled flat steel products is used for the production of subject goods.

j. **Cyclical nature of steel prices**

123. The Authority also notes that the steel prices are cyclical in nature and have remained extremely volatile over the years. The prices are subject to significant variations with prices peaking over certain periods followed by crashes.

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

K.1 Post disclosure submissions made by the domestic industry

124. Following are the post disclosure statement submissions made by the domestic industry:

- a. There is improvement in the performance of the domestic industry after the imposition of anti-dumping duty. However, there is clear likelihood that if the current anti-dumping duty is removed, there will be recurrence of injury to the domestic industry.
- b. There is decline in the capacity utilisation but the decline in capacity utilisation in the POI (A) is not due to increase in capacity only. The decline in capacity utilisation is also due to reduction in production of subject goods by applicant domestic producers in the POI (A) as compared to the previous year.
- c. Capacity utilisation in the POI is low and the domestic industry can meet higher share of domestic demand if it operates at optimum capacity utilisation.
- d. Regarding price undercutting, it is noted that the price undercutting from China PR is marginally positive. It shows that imports from China PR are competing with the domestic industry sales and are also undercutting selling price of the domestic industry.
- e. The overall price undercutting is not reflective of the actual import price since there is considerable price variation in imports from China PR and the European Union within the POI. Sales of the domestic industry are actually impacted by the low-priced imports which the domestic industry is expected to match.
- f. Negative injury margin cannot be determinative of likelihood of dumping and injury. No producer/exporter from the subject countries have participated and therefore the Authority is unable to verify the export price and the injury margin of each individual producer/exporter in subject countries. Average import price based on DGCI&S data may or may not be correct.
- g. The dumping margin during the POI from the subject countries is positive and therefore the negative injury margin should not be relied upon for assessing the need for continuation of anti-dumping duty.
- h. The primary element of consideration in a sunset review is the existence of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Therefore, negative injury margin during the POI is not determinative to assess the likelihood of injury to the domestic industry.
- i. Considering the cyclical nature of steel prices, the import prices of the PUC are likely to decline in short span of time once the prices reach the peak. If there is no anti-dumping duty in place, the domestic industry will be impacted by imports at low prices that are expected to prevail in future.
- j. In case it is established in a sunset review investigation that there is a likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, the Authority needs to continue the anti-dumping duty irrespective of the fact that injury margin is negative. Reliance is placed on the previous final findings of the Authority in following sunset review investigations:

- Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel in coils of a width upto 2100mm and thickness upto 25mm
 - Cold Rolled/cold reduced flat steel products of iron or non-alloy steel, or other alloy steel of all width and thickness - not clad, plated or coated
 - 2-Ethyl Hexanol originating in or exported from the European Union, Indonesia, Korea RP, Malaysia, Taiwan and the United States of America - No. 7/28/2020-DGTR dated 8th March 2021
 - 'Nylon Tyre Cord Fabric' originating in or exported from China PR - No. 7/22/2019-DGTR dated 29th October 2020
 - "Acetone" originating in or exported from the Korea RP, Saudi Arabia and Taiwan - No. 7/09/2019-DGTR dated 29th September 2020
 - 'Front Axle Beam' and 'Steering Knuckles' meant for heavy and medium commercial vehicles originating in or exported from China PR - No.7/26/2020-DGTR dated 24th December 2020
 - Partially Oriented Yarn (POY) originating in or exported from China PR - No. 15/27/2010-DGAD dated 10th February 2012
 - Clear Float Glass from Pakistan, Saudi Arabia and UAE: FF No. 7/3/2019-DGTR dated 07/11/2019.
 - Nonyl Phenol originating in or exported from Chinese Taipei: F.No.15/1007/2012-DGAD dated 08/11/2013.
 - Plain Medium Density Fibreboard having thickness 6mm or more originating in or exported from China PR, Malaysia, Thailand, Sri Lanka: F.No. 7/6/2020-DGTR dated 08/01/2021.
 - Carbon Black used in Rubber Applications originating in or exported from China PR and Russia: F.No. 7/15/2020-DGTR dated 22/12/2020.
 - PVC Suspension Grade Resin from China PR, Thailand and USA: F.No. 7/34/2018-DGTR dated 18/07/2019
- k. The Hon'ble Gujarat High Court in *Nirma Limited vs. UOI* [Order dated 23rd February 2017, Special Civil Application No. 16426-16427/2016] has also stated that negative injury margin cannot form the basis for determining that there is no likelihood of dumping and/or injury.
- l. The Authority should ensure that return @ 22% on capital employed on assets used for producing captive inputs is allowed if market price of captive input is not considered for determining NIP.
- m. NIP determined for colour coated steel product should be higher than NIP determined for cold rolled steel flat product because colour coated steel is a value-added product.
- n. The basic customs duty on imports of product under consideration has been reduced from 12.5% to 7.5% w.e.f. 1st February 2021 which has given leverage to the foreign exporters/Indian importers in exporting/importing the product under consideration.

K.2 Post disclosure statement submissions by other interested parties

125. No other interested party has made any submissions in response to the disclosure statement.

K.3. Examination by the Authority

126. The Authority has examined the post disclosure comments of the domestic industry and notes that most of the comments are reiterations, which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paragraphs of these final findings.
127. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below.
128. With regard to the submissions concerning determination of NIP, the Authority notes that NIP has been determined in accordance with Annexure III of the Anti-dumping Rules and the consistent practice of the Authority

129. With regard to the submission that there is decline in capacity utilisation in POI (A) due to decrease in production as well as increase in capacity, the Authority notes that capacity utilisation has declined in the POI (A) partly due to increase in capacity and partly due to decline in production during the POI (A).
130. With regard to the submission that the Authority should examine likelihood of injury and improvement in performance of domestic industry and negative injury margin is not determinative, the Authority notes that it has not relied upon only these parameters but has examined the entire gamut of information relevant for assessment of likelihood of dumping and injury. In this regard, it is noted that in *Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. vs Designated Authority*, the Hon'ble CESTAT observed as follows with regard to the examination of likelihood of injury in a situation where the condition of the domestic industry has improved:

“With respect to the injury determination, if the anti-dumping duty has had the desired effect, the condition of the Domestic Industry would be expected to have improved during the period the anti-dumping duty was in effect. Therefore, the assessment whether injury will continue, or recur, would entail a counter-factual analysis of future events, based on projected levels of dumped imports, prices, and impact on domestic producers. Thus the D.A. has to address the question as to whether the Domestic Industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted.”

131. Similarly, in *Borax Moraji Limited vs Designated Authority*, the Hon'ble Tribunal noted that:

“The expression ‘likely to lead to recurrence’ would take within its fold situation where the dumping and injury may not exist at the time of review due to the imposition and continuance of anti-dumping duty which, if allowed to cease to have effect on the expiry of five years, is likely to lead to recurrence of dumping and injury.”

132. The Authority has accordingly conducted assessment of likelihood of dumping and injury by examining what would be the likely situation of dumping from subject countries and injury to the domestic industry if the anti-dumping duty was allowed to lapse.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTERESTS AND OTHER ISSUES

133. The Authority has considered whether the continuation of anti-dumping duty would have adverse public interest. For the same, the Authority has examined whether the continuation of anti-dumping duty on the imports of the product under investigation would be against the larger public interest. This determination is based on the consideration of the information on record and interests of various parties, including the domestic industry, the importers and the users/consumers of the product.
134. The Authority issued a gazette notification inviting views concerning the subject sunset review investigation from all the interested parties, including the importers, the consumers/users and other interested parties. However, none of the interested parties have participated in the investigation and shared details with the Authority. Even though the Authority has prescribed formats for the users to quantify the impact of the anti-dumping duty and elaborate how the continuation of the anti-dumping duty would adversely impact them, it is noted that none of the importers/users have participated in the investigation and provided any relevant information.
135. The product is under freely importable category, and, therefore can be freely imported from various countries. The continuation of anti-dumping measures would not restrict the imports from the subject countries in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The continuation of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on the relative competitiveness of these products, but, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The continuation of anti-dumping measures would only remove the unfair advantages gained by the dumping practices.
136. The subject goods are used in several applications and the sectors including but not limited to construction, automotive, white goods, furniture etc. PUC offers resistance to corrosion along with barrier protection. Usage of subject goods is increasing in construction sector, production of white goods etc. due to corrosion resistant properties of subject goods.

137. It is noted that the domestic industry has submitted quantified information showing that the impact of the continuation of the anti-dumping duty shall be miniscule on the final product. As per information made available by domestic industry, it is noted that hypothetically assuming an anti-dumping duty @20% on PUC, the impact would only be insignificant i.e., 1% or less than 1% on the total value of white goods such as Refrigerators, Air-Conditioners, Washing Machines and Microwave Ovens.
138. The information of the domestic industry shows that the manufacturing facilities of the domestic industry are under-utilised and can be increased to meet higher share of domestic demand. The Authority also notes that the subject goods are supplied by the domestic industry at prices comparable to the import prices or lower than the import prices. So, the prices offered by the domestic industry are competitive prices.
139. Reference price-based duty would ensure that users and importers of product under consideration are not adversely affected when imports into India are at fair prices. Reference price-based duty also ensures that the domestic industry is not injured from low priced/unfairly priced imports into India. Thus, reference price-based duty would strike thus a fine balance between the interest of importers and users on one hand and domestic industry on the other hand in the present case.
140. The Authority notes that there are a large number of producers of the product under consideration in India and the continuation of anti-dumping duty would not lead to monopolistic or oligopolistic situation in the Indian market for the subject goods.
141. The Authority thus notes that continued reference priced based duty will ensure a safety net for domestic industry if prices reduce in near future.

M. CONCLUSION

142. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made and the facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- i. The applicant domestic producers constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application filed by the applicant on behalf of domestic producers satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
 - ii. The application contained all information relevant for the purpose of initiation of sunset review and the application contained sufficient evidence to justify initiation of the present sunset review
 - iii. The Authority considered a longer period of 18 months from October 2019 to March 2021 as POI so that it provides enough insight into the current and likely dumping and injury suffered by the domestic industry. Also, a longer POI was deemed appropriate in the present sunset review to assess the current injury/likelihood of recurrence of injury to the domestic industry caused due to the alleged dumped imports since trade in the first and second quarter of 2020-21 was impacted by Covid-19.
 - iv. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from each of the subject countries have been determined based on facts available as no producer/exporter from the subject countries has participated. The dumping margins for the subject countries are significant. Thus, there is likelihood of continuation of dumping of the subject goods from the subject countries.
 - v. The performance of the domestic industry has improved over the injury period. However, the domestic industry is vulnerable to dumping and injury in the event of cessation of duties.
 - vi. The Authority on conducting likelihood analysis has noted as under:
 - a. There are huge surplus capacities for product under consideration available with the producers/exporters in the subject countries as evidenced from the independent reports available on record.
 - b. Examination of information on record regarding export price to third countries from the subject countries shows that significant exports to third countries are at dumped /injurious prices.
 - c. Most of the countries having substantial production base for the subject goods have imposed and/or continued trade remedy measures on imports of colour coated/pre-painted flat steel products from

subject countries. Thus, the subject countries have very less options available to use the excess capacity and export to other markets.

- d. Examination of information on record regarding export price to third countries from the subject countries shows that significant exports to third countries are at prices below the export price to India, which shows that Indian market is more price attractive to producers/exporters of the subject countries.
- vii. The Authority accordingly concludes that there is a likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of revocation of duty.
- viii. Reference price-based duty recommended by the Authority in the present sunset review would ensure that users and importers of product under consideration are not adversely affected when imports into India are at fair price.

N. RECOMMENDATIONS

143. The Authority notes that the sunset review was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers/users and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Having initiated and conducted the sunset review into dumping, injury and causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in terms of provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that continued imposition of anti-dumping duty is required on subject goods from subject countries.
144. The Designated Authority accordingly considers it appropriate to recommend continuation of existing quantum and form of anti-dumping duty on the imports of subject goods from subject countries. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of existing definitive anti-dumping duty imposed vide Notification no. 49/2017-Customs (ADD) dated 17 October 2017. The Authority recommends continuation of anti-dumping duty on the imports of the subject goods described in Col. 3 of the duty table below originating in or exported from the subject countries for a period of 5 years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.
145. The anti-dumping duty is recommended as the difference between the landed value of the subject goods described in Col. 3 of the duty table below and the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below, provided the landed value is less than the value indicated in Col. 7. If the landed value is more than the value indicated in Col. 7, anti-dumping duty will not be applicable. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

DUTY TABLE

Sr. No	Heading/Sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7210, 7212, 7225 and 7226	Pre-painted, colour coated or organic coated flat steels in coils or not in coils whether or not with metallic coated substrate of zinc, aluminium zinc or any other substrate coating*	China PR	Any country including China PR	Any	822	MT	US\$
2	-do-	-do-	Any country other than China PR and	China PR	Any	822	MT	US\$

			European Union					
3	-do-	-do-	European Union	Any country including European Union	Any	822	MT	US\$
4	-do-	-do-	Any country other than China PR and European Union	European Union	Any	822	MT	US\$

*Note- The description of goods does not include plates of thickness of 6 mm or more.

O.FURTHER PROCEDURE

146. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of this Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority